



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 354]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्टूबर 1, 2019/आश्विन 9, 1941

No. 354]

NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 1, 2019/ ASVINA 9, 1941

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2019

दूरसंचार मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी प्रति पोर्ट ट्रांजेक्शन प्रभार और डिपिंग प्रभार (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2019

(2019 का 04)

सं. 15-01/2019-एफएंडईए.—भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (वर्ष 1997 का चौबीसवां) की धारा 11 की उप-धारा (1) की खंड (ख) की उप खंड (ii), (iii), (iv) तथा (v) के साथ पठित धारा 36 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, एतद्वारा दूरसंचार मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी प्रति पोर्ट ट्रांजेक्शन प्रभार और डिपिंग प्रभार (संशोधन) विनियम, 2009 में और संशोधन करने के लिए निम्नवत विनियम बनाता है, नामतः—

1. (1) इन विनियमों को दूरसंचार मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी प्रति पोर्ट ट्रांजेक्शन प्रभार और डिपिंग प्रभार (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2019 कहा जाएगा।
(2) यह विनियम दिनांक 11 नवंबर, 2019 से लागू होंगे।
2. दूरसंचार मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी प्रति पोर्ट ट्रांजेक्शन प्रभार और डिपिंग प्रभार (संशोधन) विनियम, 2009 के विनियम 3 के लिए निम्न विनियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः
“3. प्रति पोर्ट ट्रांजेक्शन प्रभार—प्रत्येक पोर्टिंग अनुरोध के लिए प्रति पोर्ट ट्रांजेक्शन प्रभार छह रुपए छियालीस पैसे मात्र होगा”

एस. के. गुप्ता, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./240/19]

टिप्पण 1: मूल विनियमों को दिनांक 20 नवम्बर, 2009 (वर्ष 2009 का नौवां) को 116-5/2009-एमएन के माध्यम से प्रकाशित किया गया था।

टिप्पण 2: मूल विनियमों को दूरसंचार मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी प्रति पोर्ट ट्रांजेक्शन प्रभार और डिपिंग प्रभार (संशोधन) विनियम, 2018 (2018 का 03) फाईल संख्या 15-1/2016-एफएंडईए द्वारा भारत सरकार के गजट, असामान्य, भाग-III, सेक्शन 4 दिनांक 31 जनवरी, 2018 के तहत प्रकाशित किया गया था।

टिप्पण 3: व्याख्यात्मक ज्ञापन दूरसंचार मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी प्रति पोर्ट ट्रांजेक्शन प्रभार और डिपिंग प्रभार (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2019 के उद्देश्यों तथा कारणों को स्पष्ट करता है।

व्याख्यात्मक ज्ञापन

1. कोई भी सब्सक्राइबर एक ही लाइसेंस सेवा क्षेत्र (एलएसए) के भीतर और साथ ही संपूर्ण देश में किसी भी लाइसेंस सेवा क्षेत्र में एक सेवा प्रदाता के स्थान पर दूसरे सेवा प्रदाता को अपनाते समय अथवा एक ही सेवा प्रदाता की एक प्रौद्योगिकी के स्थान पर दूसरी प्रौद्योगिकी को अपनाते समय अपने वर्तमान मोबाइल टेलीफोन नंबर को बनाए रख सकता है। मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी भारत में 2009 से प्रचलनरत है, जब दूरसंचार विभाग द्वारा दो मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी सेवा प्रदाताओं (एमएनपीएसपी) को मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी सेवा लाइसेंस जारी किए गए थे। दूरसंचार विभाग ने भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 के तहत भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण जारी किए गए विनियमों/आदेशों अथवा नियंत्रणों अथवा दूरसंचार विभाग (लाइसेंस प्रदाता) द्वारा लाइसेंसों में समय समय पर किए गए संशोधनों के माध्यम से जारी किए गए सभी अनुदेशों का अनुपालन करने के लिए मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी सेवा लाइसेंसधारियों को अधिदेशित किया है।
2. भारत में एमएनपी सेवाओं के कार्यान्वयन के लिए बुनियादी व्यापारिक प्रक्रिया के ढांचे को निर्धारित करने के उद्देश्य से, प्राधिकरण ने दिनांक 23 सितंबर, 2009 को दूरसंचार मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी विनियम, 2009 (2009 का 8) (एमएनपी विनियम) जारी किया। इन नियमों को समय-समय पर संशोधित किया गया है, और नवीनतम संशोधन 2018 में किया गया है।
3. दिनांक 20 नवंबर, 2009 को दूरसंचार मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी प्रति पोर्ट ट्रांजेक्शन प्रभार और डिपिंग प्रभार (संशोधन) विनियम, 2009 (एमएनपी प्रभार विनियम) को अधिसूचित करके, प्राधिकरण ने प्रति पोर्ट ट्रांजेक्शन प्रभार (पीपीटीसी) को 19/- रुपए निर्धारित किया जिसका भुगतान प्राप्तकर्ता ऑपरेटर द्वारा संबंधित एमएनपीएसपी को किया जाना था। पूर्व के वास्तविक आंकड़ों के अभाव में, यह प्रक्रिया दो एमएनपीएसपी द्वारा प्रस्तुत अनुमानित वित्तीय आंकड़ों और अन्य जानकारी के आधार पर की गई थी। प्रति पोर्ट लेनदेन प्रभार की गणना पांच वर्षों की अवधि के दौरान, एमएनपीएसपी की अनुमानित कुल लागत और पोर्टिंग उपभोक्ताओं की अनुमानित संख्या को ध्यान में रख कर किया गया था। प्राधिकरण ने पीपीटीसी की गणना करने के लिए दो एमएनपीएसपी द्वारा अनुमानित लागतों में जो भी उसपर भी विचार किया।
4. तदनुसार, दूरसंचार प्रशुल्क (उनचासावां संशोधन) आदेश, 2009 को अधिसूचित कर, प्राधिकरण ने प्रशुल्क की अधिकतम सीमा के रूप में 19/- रुपए की राशि विहित की जिसे प्रति पोर्ट लेन-देन प्रभार के रूप में प्राप्तकर्ता आपरेटर द्वारा उपभोक्ता से प्रभारित किया जा सकता था। डिपिंग प्रभार को 'फारबीयरेस' के तहत रखा गया था।
5. एमएनपी प्रभार संबंधी विनियम के विनियम 6(2) में यह उपबंध है कि "प्राधिकरण इन विनियमों के लागू होने की तिथि से एक वर्ष के अंत में प्रति पोर्ट लेनदेन प्रभार और डिपिंग चार्ज की समीक्षा और संशोधन कर सकता है"।
6. वर्ष 2018 में दोनों एमएनपीएसपी के वास्तविक वित्तीय तथा गैर वित्तीय आंकड़ों के आधार पर 'प्रति पोर्ट लेन-देन प्रभार' की समीक्षा की गई थी। तदनुसार, प्राधिकरण ने दिनांक 31 जनवरी, 2018 को दूरसंचार मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी प्रति पोर्ट ट्रांजेक्शन प्रभार और डिपिंग प्रभार (संशोधन) विनियम, 2018 जारी किया जिसके माध्यम से प्रत्येक सफल पोर्टिंग हेतु प्रति पोर्टिंग लेन-देन प्रभारों को 19/- रुपए से घटा कर 04/- रुपए कर दिया गया था। तथापि, इस संशोधन विनियम को माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा उसके दिनांक 08 मार्च, 2019 के निर्णय के माध्यम से रद्द कर दिया गया था।
7. तत्पश्चात, प्राधिकरण ने मौजूदा एमएनपी प्रक्रिया की ही समीक्षा करने के लिए एक विस्तृत सार्वजनिक परामर्श आरंभ किया। प्राधिकरण ने दिनांक 13 दिसंबर, 2018 को दूरसंचार मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (सातवां संशोधन) विनियम, 2018 जारी किया, ताकि उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए एमएनपी प्रक्रिया में कुछ बदलाव किए जा सकें। इनमें मुख्य रूप से प्रदाता आपरेटर (डीओ) के डॉटाबेस से वास्तविक समय संबंधी पूछताछ करने के पश्चात विशिष्ट पोर्टिंग कोड ('पीपीसी') को सूचित करने का उत्तरदायित्व प्रदाता आपरेटर से एमएनपीएसपी को सौंपना तथा प्रक्रिया के विभिन्न चरणों के दौरान सब्सक्राइबर को उसकी स्थिति के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए एमएनपीएसपी द्वारा सब्सक्राइबर को एसएमएस भेजना शामिल है। विनियम में एमएनपीएसपी द्वारा पहले से प्रदान की जा रही अनुषंगी सेवाओं की भी रूपरेखा प्रस्तुत की गई है नामतः, नम्बर को वापस करने का प्रभार, डॉटाबेस डॉउनलोड प्रभार, पोर्ट रद्दीकरण प्रभार, सब्सक्राइबर रीकनेक्शन प्रभार तथा नॉन-पैमेंट डिस्कनेक्शन प्रभार।
8. उपर्युक्त के आलोक में, प्राधिकरण ने दिनांक 22 फरवरी, 2019 को परामर्श पत्र जारी करके मौजूदा एमएनपी प्रभार विनियमों की समीक्षा करने के लिए एक सार्वजनिक परामर्श प्रक्रिया आरम्भ की। (जिन्हें बाद में, जैसा कि उपर वर्णित है, माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार अद्यतन किया गया)। हितधारकों से टिप्पणियां और प्रति-टिप्पणियां प्राप्त करने के लिए अंतिम तिथि क्रमशः 15 मार्च, 2019 और 22 मार्च, 2019 थी। तथापि, हितधारकों के अनुरोधों पर विचार करते हुए, हितधारकों से टिप्पणियां और प्रति-टिप्पणियां प्राप्त करने की अंतिम तिथि को क्रमशः दिनांक 12 अप्रैल, 2019 तथा 19 अप्रैल, 2019 तक बढ़ा दिया गया था। इस संबंध में दिनांक 27 मई, 2019 को एक खुला मंच चर्चा भी आयोजित की गई थी। एमएनपीएसपी तथा टीएसपी ने खुला मंच चर्चा के पश्चात भी आगे की अतिरिक्त टिप्पणियां भी प्रस्तुत की हैं।
9. दिनांक 07 मई, 2019 के पत्र तथा उत्तरवर्ती अनुस्मारकों के माध्यम से, दो एमएनपीएसपी को वित्त वर्ष 2018–19 के लिए लेखापरीक्षित वार्षिक लेखाओं की प्रतियों के साथ पूँजीगत व्यय (केपेक्स) तथा प्रचालन व्यय (ओपेक्स) का ब्योरा उपलब्ध कराने को कहा गया था। वित्त वर्ष 2018–19 के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों को मैसर्स सिनीवर्स द्वारा दिनांक 22 जुलाई, 2019 को प्रस्तुत किया गया था। मैसर्स एमएनपी इंटरकनेक्शन टेलीकाम सॉल्यूशन्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एमआईटीएस) ने वित्त वर्ष 2018–19 के लिए एमएनपी व्यापार के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों को दिनांक 28 जून, 2019 को प्रस्तुत किया।
10. प्रमुख दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) को 7वें संशोधन के परिणामस्वरूप किए जाने वाले अतिरिक्त कार्य और दिनांक 25 जून, 2019 के पत्र के माध्यम से होने वाले संभावित व्यय के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की आवश्यकता के लिए लागत हेतु किए जाने वाले निवेश का ब्योरा प्रदान करने को कहा गया था, उनके उत्तर पर भी प्राधिकरण द्वारा विचार किया गया था।

¹ अनुषंगी सेवाओं का ब्योरा व्याख्यात्मक ज्ञापन के उत्तरवर्ती अनुच्छेदों में दिया गया है, जहां पर अनुषंगी प्रभारों के मुद्दे पर विचार किया गया है।

11. दोनों एमएनपीएसपी ने 7 वें संशोधन के परिणामस्वरूप किए जाने वाले आवश्यक अतिरिक्त कार्य के लिए अनुमान भी प्रस्तुत किया है। दोनों एमएनपीएसपी को अतिरिक्त व्यय के औचित्य के साथ एमएनपी प्रक्रिया में बदलाव को लागू करने के लिए आवश्यक ढांचे और अतिरिक्त हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर पर एक प्रस्तुति देने के लिए बुलाया गया था, जिसे दोनों एमएनपीएसपी द्वारा दिनांक 24 जुलाई, 2019 को प्रस्तुत किया गया था। प्रस्तुति के दौरान, दोनों एमएनपीएसपी द्वारा यह बात इंगित की गई थी कि 7 वें संशोधन के कार्यान्वयन के लिए दिए गए अतिरिक्त लागत अनुमानों में चल रहे /मौजूदा व्यवस्था के साथ-साथ 7वें संशोधन के तहत परिकल्पित परिवर्तन को लागू करने के लिए लागत शामिल है। तदनुसार, दोनों को दो लागत घटकों को अलग करने के लिए कहा गया था। एक एमएनपीएसपी ने दिनांक 28 जुलाई, 2019 को चालू प्रचालनों और 7वें संशोधन संबंधी आवश्यकताओं के बीच लागत को विभाजित करने के बाद संशोधित लागत अनुमान प्रस्तुत किया। अन्य एमएनपीएसपी ने दिनांक 02 अगस्त, 2019 के पत्र के माध्यम से यह जानकारी प्रदान की कि इस प्रकार का पृथक्कीकरण करना संभव नहीं है।
12. परामर्श प्रक्रिया के दौरान प्राप्त टिप्पणियों तथा प्रति- टिप्पणियों के आधार पर खुला मंच चर्चा में हुए विचार- विमर्श तथा तत्पश्चात् एमएनपीएसपी और अन्य हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियों के आधार पर, प्राधिकरण ने दिनांक 16 अगस्त, 2019 को मसौदा “दूरसंचार मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी प्रति पोर्ट ट्रांजेक्शन प्रभार तथा लिंगिंग प्रभार (संशोधन) विनियम, 2019” (मसौदा विनियम) जारी किए। हितधारकों से मसौदा विनियम पर दिनांक 23 अगस्त, 2019 तक अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था। तथापि, हितधारकों (एमएनपीएसपी) के अनुरोधों पर विचार करते हुए, टिप्पणियां प्राप्त करने की अंतिम तिथि को दिनांक 28 अगस्त, 2019 तक बढ़ा दिया गया था।
13. पैरा 14 से 46 में मसौदा विनियम हेतु मूलभूत तर्कधार तथा परामर्श पत्र में उठाए गए प्रश्नों पर चर्चा की गई है। तत्पश्चात्, पैरा 47 में मसौदा विनियम को जारी किए जाने (अथात् 16 अगस्त, 2019 के पश्चात्) के उपरांत प्राप्त जानकारी पर चर्चा की गई है।
- परामर्श पत्र में उठाए गए मुद्दे तथा प्राधिकरण द्वारा निर्णय पर विचार किए जाने हेतु सूचनाओं का विश्लेषण
14. पूर्वगामी चर्चा के महेनजर, मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी प्रति पोर्ट ट्रांजेक्शन प्रभार और अन्य शुल्क की समीक्षा पर हितधारकों के विचार प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित प्रश्न उठाए गए थे। परामर्श पत्र सहित हितधारकों की लिखित टिप्पणियां और प्रति टिप्पणियां www.trai.gov.in पर उपलब्ध हैं। उत्तरवर्ती पैराओं में, प्राधिकरण के निष्कर्ष और निर्णय के पीछे के तर्क सहित परामर्श पत्र में उठाए गए मुद्दों का संक्षिप्त वर्णन किया गया है।
- क्या पूर्व में की गई समीक्षा के आधार पर भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा अपनाई गई पद्धति के आधार पर ‘प्रति पोर्ट ट्रांजेक्शन प्रभार’ का परिकलन जारी रखना चाहिए? यदि नहीं, तो कृपया पद्धति का सुझाव देते हुए हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और अन्य संसाधनों आदि की लागतों का उल्लेख भी करें।
15. कुछ हितधारकों ने उल्लेख किया है कि मौजूदा पद्धति को जारी रखा जाना चाहिए, जबकि कुछ अन्य ने कुछ संशोधनों का सुझाव दिया है। एक एमएनपीएसपी ने अन्य बातों के साथ-साथ यह सुझाव दिया है कि प्रशुल्क की समीक्षा वार्षिक आधार की बजाय पांच वर्ष के आधार पर होनी चाहिए जबकि अन्य एमएनपीएसपी ने प्रत्येक तीन वर्षों में इसकी समीक्षा करने का सुझाव दिया। उनके द्वारा यह तर्क दिया गया है कि प्रशुल्क परिकलन के लिए उपयोग किए जाने वाले मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी की प्रमात्रा, ‘अनावर्ती पोर्टिंग संख्या में परिवर्तनों को समायोजित करने के पश्चात् पर्याप्त रूप से लंबी अवधि पर आधारित होनी चाहिए, टीएसपी द्वारा विलम्ब से भुगतान किए जाने के कारण कार्यशील पूँजी की आवश्यकता को एक माह से तीन महीने में परिवर्तित कर दिया जाना चाहिए, नियोजित पूँजी पर लाभ 15 प्रतिशत से भी अधिक होना चाहिए, आदि। एमएनपीएसपी द्वारा भी नियेदन किया गया है कि उनके द्वारा बहन की गई सभी लागतों पर विचार किया जाना चाहिए और वास्तविक व्यवसाय लागत जिसके लिए रिकॉर्ड पर साक्ष्य हैं, को अस्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। इसके अलावा, पीपीटीसी का परिकलन करने के लिए एक एमएनपीएसपी ने उल्लेख किया कि एमएनपीएसपी की दोनों लागतों (प्रचालन और व्यवसाय) में से जो कम हो उसकी बजाय दोनों लागतों के औसत पर विचार किया जाना चाहिए। चूंकि दोनों एमएनपीएसपी पृथक परिवेश में कार्य करते हैं और दोनों का औसत अंगीकार करना सबसे अच्छा और उचित तरीका होगा। उन्होंने यह सुझाव दिया है कि पीपीटीसी समय के साथ स्थिर होनी चाहिए और छह माह की मूल्य कार्यान्वयन अवधि के साथ 3 वर्ष उपरांत समीक्षा की जानी चाहिए। एक एमएनपीएसपी ने यह उल्लेख किया कि दोनों एमएनपीएसपी के बीच कम लागतों की ‘चौरी पिंकिंग’ नहीं की जानी चाहिए और एक एमएनपीएसपी की लागत को समग्र रूप से लिया जाना चाहिए।
16. इस संबंध में, एक अन्य हितधारक ने उल्लेख किया है कि भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण को दोनों ‘एमएनपीएसपी’ की ‘लागतों’ में से कम लागत पर आधारित किया जाना चाहिए, क्योंकि दोनों ‘एमएनपीएसपी’ की लागत का औसत एक कुशल ‘एमएनपीएसपी’ की लागत को नहीं दर्शाएगा, जिससे अकुशल ‘एमएनपीएसपी’ को सहायता प्रदान कर मोबाइल ऑपरेटर (एमएनओ) प्रतिकूल रूप से प्रभावित होंगे। इसके अलावा, लागत गणना में अशाय्य ऋणों के लिए प्रावधान किए जाने के परिणामस्वरूप वे एमएनओ प्रतिकूल रूप से प्रभावित होंगे जो एमएनपीएसपी को समय से भुगतान करते हैं। एमएनओ द्वारा भुगतान नहीं किए जाने/विलम्ब से भुगतान करने संबंधी मामलों को विधिक ढांचे के तहत एमएनपीएसपी तथा एमएनओ के बीच सुलझाया जाना चाहिए। कुछ हितधारकों द्वारा यह भी उल्लेख किया गया कि एमएनओ से रॉयल्टी/परामर्श/लाइसेंसिंग की लागत शाश्वत रूप से नहीं वसूली जा सकती है।
17. एक अन्य हितधारक ने टिप्पणी की है कि दोनों एमएनपीएसपी एकाधिकार वाले बाजार में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, क्योंकि उनके संबंधित क्षेत्रों में एमएनपी सेवाओं का कोई अन्य आपूर्तिकर्ता नहीं है। ऐसे परिवृद्धि में, यह अनिवार्य है कि प्रभारों को लागत इत्यादि के आधार पर निर्धारित किया जाए ताकि एमएनपीएसपी को कोई अनुचित लाभ प्राप्त नहीं हो।
18. कुछ हितधारकों ने उल्लेख किया है कि हाल ही में पोर्ट की लागतों में पर्याप्त वृद्धि हुए बिना ‘पोर्ट की संख्या’ में उल्लेखनीय वृद्धि होने के कारण एमएनपीएसपी पहले ही सभी लागतों की वसूली करने के उपरांत अधिक राशि अर्जित कर चुके हैं। उन्होंने सुझाव दिया है कि एमएनपीएसपी द्वारा की गई अधिक वसूली की पीपीटीसी की भावी गणना में समायोजित किया जाना चाहिए।

19. एक हितधारक ने टिप्पणी की है कि 7वें संशोधन के कार्यान्वयन के लिए एमएनपीएसपी द्वारा वहन की गई लागत में वास्तविक रूप से कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि मोटे तौर पर एमएनपीएसपी अपनी ओर से 'मार्जिनल हार्डवेयर,' 'सॉफ्टवेयर' और प्रचालन लागत के साथ परिवर्तित प्रक्रियाओं को लागू करने के लिए एमएनओ के मौजूदा नेटवर्क का उपयोग करेंगे। यह उल्लेख किया गया है कि अतिरिक्त लागत एमएनपीएसपी की मौजूदा लागत का लगभग 1 से 3 प्रतिशत होगी। इस संबंध में, एक एमएनपीएसपी ने टिप्पणी की है कि 1 से 3 प्रतिशत संबंधी धारणा का अनुमान लगा पाना काफी जल्दबाजी साबित होगा और इन लागतों का सटीक अनुमान लगा पाना टीएसपी के क्षेत्राधिकार से परे है।
20. अन्य हितधारक ने टिप्पणी की है कि एमएनपीएसपी के वास्तविक लेखापरीक्षित आंकड़ों और संशोधित प्रक्रिया के तहत वहन की जाने वाली लागत संबंधी अनुमानों के आधार पर समीक्षा की जानी चाहिए। तथापि, प्राधिकरण को एक वर्ष उपरांत आगे की समीक्षा करने संबंधी प्रावधान को बनाए रखना चाहिए जब वास्तविक लेखापरीक्षित वित्तीय तथा गैर-वित्तीय आंकड़े उपलब्ध होंगे। यह भी उल्लेख किया गया है कि किए गए सभी पोर्टिंग अनुरोधों पर विचार करते हुए प्रति पोर्ट ट्रांजेक्शन प्रभार का परिकलन करने के लिए, दोनों एमएनपीएसपी हेतु पृथक् प्रक्रिया की जानी चाहिए। इस संख्या तक रद्द अथवा अस्वीकृत अनुरोधों के प्रतिशत के आधार पर पहुंचा जाना चाहिए। तत्पश्चात्, दोनों एमएनपीएसपी हेतु प्रति पोर्ट ट्रांजेक्शन प्रभार का परिकलन करने के लिए अनुषंगी सेवाओं हेतु प्रभार को जोड़ा जा सकता है। यह भी सुझाव दिया गया है कि इन संख्याओं में सबसे कम संख्या को प्रति पोर्ट ट्रांजेक्शन प्रभार निर्धारित किया जाना चाहिए, चूंकि भारतीय उपभोक्ताओं को किसी एमएनपीएसपी के अकार्यक्षम होने के कारण खराब सेवाओं का सामना नहीं करना पड़े। इस बिंदु के संबंध में एक एमएनपीएसपी ने टिप्पणी की कि असफल पोर्ट को मार्क करने की यह पद्धति से ऐसे आपरेटरों को लाभ पहुंचेगा जो निष्क्रिय पोर्ट की जानकारी प्रदान करते हैं जिससे भारी संख्या में त्रुटियां होंगी। तत्पश्चात्, इन असफल पोर्टों की लागत का भुगतान अन्य आपरेटरों द्वारा किया जाएगा जिनके बेहतर प्रक्रियाएं तथा नियंत्रण होते हैं। इसके अलावा, यह कहा जाता है कि इस पद्धति में असफल तथा सफल पोर्टों का अनुपात स्थिर बना रहता है, जोकि सत्य नहीं है।
21. एक हितधारक ने उल्लेख किया कि प्राधिकरण को एमएनपीएसपी के वर्ष 2017–18 और वर्ष 2018–19 सहित वित्तीय और गैर-वित्तीय आंकड़ों और उनकी अनुमानित लागतों को साझा करना चाहिए ताकि अन्य हितधारकों के साथ विस्तृत परामर्श किया जा सके। दोनों हितधारी एमएनपीएसपी ने खुला मंच चर्चा में इस कथन को मानने से इंकार किया तथा कहा कि ऐसा नहीं किया जाना चाहिए।
22. एक हितधारी ने उल्लेख किया कि प्रति पोर्ट ट्रांजेक्शन प्रभार के अतिरिक्त यूपीसी अनुरोध का सृजन करने के लिए, दाता प्रचालक से पूछताछ किए जाने, यूपीसी अथवा अस्वीकृति का कारण का सृजन करने, उस यूपीसी अथवा अस्वीकृति के कारण को प्रेषित करने के लिए पृथक् प्रभार होने चाहिए चूंकि एमएनपीएसपी द्वारा सातवें संशोधन का अनुपालन करने के लिए पर्याप्त तथा वृद्धिशील लागतें होती हैं। इस संबंध में अन्य हितधारक ने टिप्पणी की कि सभी लागतों को पीपीटीसी के तहत सम्मिलित किया जाना चाहिए क्योंकि यूपीसी अनुरोध के सृजन का अभिप्राय होगा कि दाता प्रचालक को एमएनपीएसपी को भुगतान करने के लिए यूपीसी सृजन संबंधी क्रियाकलापों के लिए सब्सक्राइबरों को प्रभारित करने की आवश्यकता होगी, जोकि उपभोक्ताओं के हितों के लिए घातक होगा।
23. अनेक हितधारकों ने भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा लागत परिकलन से रॉयल्टी तथा परामर्श संबंधी प्रभार को हटाने की सिफारिश की है। अन्य हितधारक ने यह भी उल्लेख किया कि लाइसेंसिंग तथा रॉयल्टी से संबंधित कुल लागत पर छूट प्रदान की जानी चाहिए, क्योंकि इतनी लंबी अवधि के लिए एक साधारण विनियामक प्रक्रिया पर इसे लागू नहीं किया जाना चाहिए। हितधारकों ने यह भी टिप्पणियां की हैं कि ऐसी लागतें शाश्वत रूप से वसूली जा रही हैं जबकि एमएनपीएसपी को पर्याप्त विशेषज्ञता क्यों न प्राप्त हो गई हो।

विश्लेषण

24. प्राधिकरण ने प्रस्तुत किए गए उल्लेखों तथा इसमें शामिल मुद्दों का विश्लेषण किया। प्राधिकरण ने मोबाइल नम्बर प्रति पोर्ट पोर्टेबिलिटी प्रभार का परिकलन करने के लिए निम्न पर विचार करने का निर्णय लिया:
- 24.1 वर्ष 2009 के विपरीत जब पीपीटीसी को पिछले लागत आंकड़ों के अनुपलब्ध होने पर प्रारंभिक रूप से परिकलित किया गया था, वर्तमान में, पिछले वर्ष की लेखापरीक्षित ऐतिहासिक लागत डॉटा के संबंध में पर्याप्त जानकारी प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। तदनुसार, प्राधिकरण ने मौजूदा एमएनपी प्रक्रिया के लिए पीपीटीसी का परिकलन करने हेतु लेखापरीक्षित ऐतिहासिक लागत डॉटा को आधार के रूप में उपयोग करने का निर्णय लिया। इसके अलावा, सातवें संशोधन के अंतर्गत एमएनपी प्रक्रिया में कठिपय परिवर्तन किए गए थे जिसके लिए एमएनपीएसपी को मौजूदा व्यवस्था में कठिपय संशोधन करने की आवश्यकता हो सकती है। तदनुसार, प्राधिकरण ने सातवें संशोधन के कार्यान्वयन में संभावित अतिरिक्त लागत के संबंध में हितधारकों से लागत संबंधी अनुमान मांगे ताकि पीपीटीसी का परिकलन करते समय उनपर उपयुक्त रूप से विचार किया जा सके। एमएनपीएसपी द्वारा सातवें संशोधन के कार्यान्वयन में संभावित अतिरिक्त कार्य के संबंध में पीपीटीसी के इंकिमेंटल लागत घटक का परिकलन करने के लिए सभी हितधारकों से प्राप्त प्रतिक्रिया पर विचार किया गया है।
- 24.2 पीपीटीसी की गणना के लिए लागत और पोर्ट वॉल्यूम डॉटा के संबंध में, एक एमएनपीएसपी ने पीपीटीसी को निर्धारित करने के लिए तीन वर्ष की लागत और पोर्ट वॉल्यूम डॉटा का उपयोग करने का सुझाव दिया। अन्य एमएनपीएसपी ने पिछले पांच वित्तीय वर्षों की पोर्ट प्रमात्रा पर विचार करने का सुझाव दिया है। इस संबंध में, प्राधिकरण ने पाया कि पोर्ट की प्रमात्रा में पिछले कुछ वर्षों में कुछ अस्थिरता देखी गई है। पोर्टिंग प्रमात्रा वर्ष 2016–17 में 636 लाख से बढ़कर वर्ष 2017–18 में 981 लाख और वर्ष 2018–19 में 576 लाख हो गई। इसलिए, प्राधिकरण ने पोर्टिंग प्रमात्रा और लागत के उचित अनुमान प्राप्त करने का निर्णय लिया। पर्याप्त संख्या में वर्षों का औसत लेना आवश्यक हो सकता है, ताकि कुछ वर्षों के उच्च या निम्न परिणामों को विकृत न करें। इसके अलावा, जुलाई, 2015 में भारत में पूर्ण मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी की शुरूआत की गई थी। अतएव, तत्पश्चात् पोर्टिंग प्रमात्राओं की तुलना करना तर्कसंगत होगा, क्योंकि वे पहले की प्रमात्राओं की तुलना में अधिक उचित और सटीक अनुमान देंगे, जब केवल इंट्रासिकिल एमएनपी की व्यवस्था ही मौजूद थी। एक एमएनपीएसपी द्वारा भी यह सुझाव दिया गया है। इन सब कारणों से प्राधिकरण ने प्रति पोर्ट ट्रांजेक्शन प्रभार (पीपीटीसी) का परिकलन करने के लिए वर्ष 2016–17 से 2018–19 तक तीन वर्षों की अवधि की लागत और पोर्टिंग प्रमात्रा के औसत पर विचार करने का निर्णय लिया।

- 24.3 एमएनपीएसपी ने यह भी उल्लेख किया है कि पीपीटीसी का निर्धारण करने के लिए प्रत्येक एमएनपीएसपी की कुल और वास्तविक लागतों को संपूर्ण माना जाना चाहिए। इस अनुरोध के महेनजर और भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के आर्थिक रूप से सबसे कुशल आपरेटर की लागत के आधार पर प्रशुल्क का निर्धारण करने की मानक पद्धति के महेनजर, प्राधिकरण ने पीपीटीसी (रॉयल्टी/लाइसेंस शुल्क, जैसा कि लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों में दर्शाया गया है, सहित) का निर्धारण करने के लिए दोनों एमएनपीएसपी की कुल लागतों में से 'कम' को अंगीकार करने का निर्णय लिया। इस संबंध में एमएनपीएसपी ने धारणा व्यक्त की है कि दोनों एमएनपीएसपी में से कम लागत वाले एमएनपीएसपी की अपेक्षा दोनों एमएनपीएसपी की औसत लागत पर विचार किया जाना चाहिए चूंकि वे भिन्न-भिन्न परिवेश में प्रचालन करते हैं। तथापि, प्राधिकरण ने यह निर्णय लिया कि किसी अकुशल आपरेटर को उसकी अकुशलता के लिए उच्च लागत ढांचे पर आधारित उच्च प्रशुल्क निर्धारण कर पुरस्कृत नहीं किया जाना चाहिए। कुशल आपरेटर के लागत ढांचे पर आधारित एक तर्कसंगत प्रशुल्क निर्धारण करने से अकुशल आपरेटर अपनी लागत को कम करके अपने प्रचालनों में कुशलता प्राप्त करने के लिए बाध्य होगा। इसके अलावा, उच्च प्रशुल्क का निर्णय लेना प्राप्तकर्ता प्रचालक/उपभोक्ता तथा संपूर्ण टेलिकॉम सेक्टर के लिए घातक होगा।
- 24.4 एक एमएनपीएसपी ने यह भी निवेदन किया है कि ऑपरेटरों द्वारा भुगतान नहीं किए जाने अथवा विलंब से भुगतान किए जाने के परिणामस्वरूप एमएनपीएसपी द्वारा अशोध्य ऋणों को भी पीपीटीसी का परिकलन करते समय एक लागत घटक के रूप में माना जाना चाहिए। प्राधिकरण ने इस मुद्रे पर सावधानीपूर्वक विचार किया है और यह निर्धारित किया है कि एमएनपीएसपी और ऑपरेटरों के बीच भुगतान नहीं किया जाना अर्थात् विलंब से भुगतान किया जाना, दोनों के बीच एक वाणिज्यिक विवाद है और पीपीटीसी का परिकलन करते हुए यह लागत घटक नहीं हो सकता है। पीपीटीसी की संगणना में अशोध्य ऋणों के अवशोषण से एमएनपीएसपी हतोत्साहित होगा जिससे वह बकाया ऋणों की वसूली के लिए सद्भाव से कार्यवाही नहीं करेगा। इसके अलावा, जैसा कि अन्य हितधारकों द्वारा टिप्पणी की गई है कि लागत में अशोध्य ऋणों के लिए प्रावधान किए जाने से पीपीटीसी बढ़ जाएगी, जो कि एमएनओ पर जुर्माना लगाए जाने के समान होगा जोकि बढ़े हुए पीपीटीसी के रूप में एमएनपीएसपी को समय से भुगतान करते हैं। इन कारणों से प्राधिकरण ने पीपीटीसी का परिकलन करने के प्रयोजनार्थ अशोध्य ऋणों को लागत घटक के रूप में वर्जित किए जाने का निर्णय लिया।
- 24.5 प्राधिकरण ने इसमें शामिल लागतों का निर्धारण करने के लिए दो एमएनपीएसपी के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों पर भी विचार करने का निर्णय लिया था। यह सुनिश्चित करता है कि लागत अनुमान पर आधारित नहीं है, और एमएनपीएसपी द्वारा अपनी सेवाएं प्रदान करने में लगने वाली वास्तविक लागत हैं।
- 24.5 एमएनपीएसपी द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान वहन की गई लागतों के विश्लेषण से, यह देखा गया है कि एक एमएनएसपी के लिए परामर्श और संबंधित शुल्कों पर आने वाली लागत लगभग 80 प्रतिशत है, जो कि अधिक है।
- 24.7 दोनों एमएनपीएसपी ने वर्तमान 15 प्रतिशत के मुकाबले नियोजित पूंजी पर लाभ (आरओसीई) (एक एमएनपीएसपी द्वारा 35 प्रतिशत सुझाया गया) को बढ़ाने का सुझाव दिया है। एमएनपीएसपी ने आरओसीई में वृद्धि करने के कारणों में मुख्यतः करों की दरें, मुद्रास्फीति, विधिक लागत और मुद्रा में उत्तर-चढ़ाव का उल्लेख किया है। इन पर नीचे चर्चा की गई है:
- (क) कर दरें पूर्व के दृष्टिकोण से पता चलता है कि 15 प्रतिशत की दर से आरओसीई में लागू दरों में कर का तत्व भी शामिल है। इसलिए, जब तक कि लागू कर की दरों में पर्याप्त परिवर्तन नहीं होता है, प्राधिकरण को आरओसीई दरों में समायोजन करने का कोई कारण नजर नहीं आता है।
- (ख) मुद्रास्फीति: मुद्रास्फीति, कंपनी की पूर्व की लागत ढांचे में परिलक्षित होती है जो हर साल अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की मौजूदा दर के साथ बदल जाती है। वर्तमान मामले में, प्राधिकरण ने पहले ही प्रशुल्क का निर्धारण करने के लिए एमएनपीएसपी की पूर्व की लागतों पर विचार किया है और इसलिए, दोबारा मुद्रास्फीति के लिए आरओसीई को पुनः समायोजित किए जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा, मौजूदा आरओसीई में मुद्रास्फीति का पहले से सम्मिलित किया गया है।
- (ग) विधिक लागतें: इन पर पहले से ही एमएनपीएसपी की पूर्व की लागत के भाग के रूप में विचार किया गया है और आरओसीई में इसके लिए पुनः अन्य प्रावधान किए जाने से विधिक खर्चों का दोहरा लेखांकन हो जाएगा।
- (घ) मुद्रा में उत्तर-चढ़ाव: मुद्रा में उत्तर-चढ़ाव की प्रमात्रा, जैसा कि एमएनपीएसपी के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण में परिलक्षित होता है, अत्यंत कम है और इसलिए, यह समग्र आरओसीई निर्धारण को प्रभावित नहीं करेगा। इसके अलावा, मुद्रा में उत्तर-चढ़ाव से नुकसान के साथ-साथ लाभ भी हो सकता है जोकि विनियम दर की चाल पर निर्भर करेगा। इसलिए, इस प्रकार की कवायद में मुद्रा के उत्तर-चढ़ाव पर विचार किए जाने का कोई लाभ नहीं है।
- 24.8 अतः प्राधिकरण निर्धारित करता है कि 35 प्रतिशत की दर से आरओसीई अत्यधिक है और 15 प्रतिशत की दर से नियोजित पूंजी पर लाभ एक युक्तिसंगत लाभ है। इसलिए, प्राधिकरण ने मौजूदा पद्धति के अनुरूप, कुल लागत का निर्धारण करने के लिए 15 प्रतिशत की दर से नियोजित पूंजी पर लाभ प्रदान करने पर विचार किया है।
- 'प्रति पोर्ट ट्रांजेक्शन प्रभार' का परिकलन करते हुए, क्या एमएनपीएसपी को प्राप्त एमएनपी अनुरोधों की कुल संख्या अथवा सफलतापूर्वक पोर्ट किए गए नम्बरों पर विचार किया जा सकता है? कृपया अपने उत्तर का औचित्य सिद्ध करें।
25. इस संबंध में, अधिकांश हितधारकों ने टिप्पणियां की हैं कि पीपीटीसी का परिकलन करते हुए, एमएनपीएसपी को प्राप्त एमएनपी अनुरोधों की कुल संख्या पर विचार किया जाना चाहिए। कुछ अन्य ने टिप्पणी की है कि पीपीटीसी की गणना करने के लिए केवल सफल पोर्टिंग अनुरोधों पर विचार किया जाना चाहिए। इस संबंध में, एक हितधारक ने टिप्पणी की है कि 7वें संसोधन के कार्यान्वयन के साथ, पोर्टिंग अनुरोधों और सफल पोर्ट के बीच अंतर कम हो जाएगा और इसलिए एमएनपीएसपी पर इसका कोई इतना व्यापक वित्तीय प्रभाव नहीं होगा। एक अन्य हितधारक ने टिप्पणी की है कि असफल पोर्टिंग के मामले में भी एमएनपीएसपी को व्यय करना पड़ता है, यहां तक कि असफल पोर्टिंग जो आमतौर पर सफल पोर्टिंग की तुलना में अधिक महंगी होती है। यह भी निवेदन किया गया था कि कुल पोर्ट अनुरोधों के आधार पर पीपीटीसी की तुलना में असफल पोर्टिंग अनुरोधों पर आधारित पीपीटीसी अधिक होगी। इसलिए, जो उपभोक्ता सफलतापूर्वक पोर्ट होते हैं, वे अंततः गैर-गंभीर सब्सक्राइबरों अथवा गलत दस्तावेज प्रस्तुत करने वाले सब्सक्राइबरों द्वारा किए गए निःशुल्क पोर्टिंग प्रयासों को सम्बिद्धी प्रदान करते हैं और उनके लिए भुगतान करते हैं।

विश्लेषण

26. इस संबंध में, प्राधिकरण ने पाया कि कुल पोर्टिंग अनुरोधों और सफल पोर्टिंग के बीच का अंतर पिछले कुछ वर्षों से कम हो रहा है और 7 वें संशोधन के लागू होने के बाद इसके और अधिक कम होने की संभावना है। इसके अलावा, एमएनपीएसपी को असफल पोर्टिंग अनुरोधों पर भी खर्च उठाना पड़ता है। इसके अलावा, कई मामलों में, पोर्टिंग अनुरोध की विफलता एमएनपीएसपी के नियंत्रण से परे कारणों के चलते हो सकती है। इसलिए, प्राधिकरण ने पीपीटीसी निर्धारित करने के लिए प्रत्येक पोर्टिंग अनुरोध पर विचार करने का निर्णय लिया। जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया है, अधिकांश हितधारकों ने भी पोर्टिंग के अनुरोधों की कुल संख्या पर विचार करने का सुझाव दिया है।

पीपीटीसी का निर्धारण

27. उपरोक्त विचारों के आधार पर, एमएनपीएसपी द्वारा प्रदान की गई मौजूदा सेवाओं के लिए प्राधिकरण ने निम्नलिखित पीपीटीसी का परिकलन किया है:

व्योरा	इकाई	राशि
कर्मचारियों पर लागत [#]	लाख में	1318.37
प्रसाशनिक एवं अन्य लागत [#]		2452.93
कंसल्टेंसी / रोयाल्टी चार्जेंज [#]		1049.27
डिप्रेशिएशन एवं एमोर्टाइजेशन [#]		94.09
आरओसीई @ 15% [#]		1096.53
तीन वर्षों के लिए कुल लागत*	लाख रुपये में	6011.19
तीन वर्षों में असल पोर्टिंग	लाख में	1102.08
प्रति पोर्ट पोर्टिंग प्रभार	रुपये में	5.45

* अशोध्य ऋणों/अशोध्य ऋणों और विदेशी वित्तिय हानियों के लिए प्रावधान के अलावा (यहां तक कि यदि विदेशी मुद्रा से होने वाले घाटे पर विचार किया जाता है, तो यह पीपीटीसी गणना पर व्यापक प्रभाव नहीं डालेगा) यह संबंधित एमएनपीएसपी की कुल लागत पर आधारित है। इसमें 15 प्रतिशत की दर से आरओसीई भी शामिल है। लागत पूँजी को वित्तीय वर्ष के अंत तक फिर्स्त एसेट्स, वर्क इन प्रोग्रेस में लगे कुल पूँजी तथा नेट वर्किंग कैपिटल (वर्तमान संपत्ति – वर्तमान देनदारियों) को शामिल कर निर्धारित किया गया है।

तीन वित्तीय वर्षों की एग्रीगेट वैल्यू 2016–17, 2017–18 और 2018–19

पीपीटीसी का वृद्धिशील घटक

28. सातवां संशोधन, जैसा कि पहले चर्चा की गई है, डीओ डॉटाबेस से वास्तविक समय आधारित पूछताछ के बाद डीओ के बजाय एमएनपीएसपी द्वारा यूपीसी सूजन और एमएनपीएसपी द्वारा सब्सक्राइबर को स्टेट्स नोटिफिकेशन भेजना जैसी एमएनपी प्रक्रिया के प्रवाह में कतिपय परिवर्तन का उपबंध करता है। 7 वें संशोधन के तहत परिकल्पित परिवर्तनों को लागू करने के लिए एमएनपीएसपी कतिपय केपेक्स और ओपेक्स लागत व्यय करनी पड़ सकती है। तदनुसार, 7 वें संशोधन के कार्यान्वयन के लिए अतिरिक्त कार्य हेतु पीपीटीसी के वृद्धिशील घटक का परिकलन करने के लिए, प्राधिकरण ने 7 वें संशोधन के कार्यान्वयन के लिए किए जाने वाले अतिरिक्त कार्य के संबंध में एमएनपीएसपी और टीएसपी से लागत अनुमान भी मांगा। तथापि, ऐसे एमएनपीएसपी द्वारा दिए गए लागत का अनुमान, जिसकी कुल लागत कम है, में चल रहे/मौजूदा प्रचालनों के साथ-साथ 7 वें संशोधन के तहत परिकल्पित अतिरिक्त कार्य को सहायता प्रदान करने के लिए लागतें शामिल हैं। बास-बार अनुरोध करने के बावजूद, उक्त एमएनपीएसपी द्वारा दो लागत घटकों के पृथक करने के संबंध में आंकड़े प्राधिकरण को प्रदान नहीं किए गए हैं। तदनुसार, प्राधिकरण ने 7 वें संशोधन के कार्यान्वयन से जुड़े अतिरिक्त कार्यों के लिए पीपीटीसी के वृद्धिशील घटक का निर्धारण करने के लिए एमएनपीएसपी और टीएसपी (जो वर्तमान में यूपीसी सूजन और संबंधित प्रक्रियाओं में लगे हुए हैं) सहित हितधारकों द्वारा प्रदान किए गए आंकड़ों का उपयोग किया है।
29. एमएनपीएसपी ने यह उल्लेख किया है कि उन्हें वृद्धिशील उत्तरदायितों को पूरा करने के लिए कर्मियों को जोड़ने की आवश्यकता है। तथापि, प्राधिकरण ने यह पाया कि 7 वें संशोधन के परिणामस्वरूप किए जाने वाले अतिरिक्त कार्य काफी हद तक स्वचालित होंगे तथा बिना किसी अर्थव्यवस्था न्यूनतम मानव हस्तक्षेप के साथ किया जाएगा और एमएनपीएसपी द्वारा मौजूदा प्रचालन में तैनात किए गए मौजूदा कर्मी 7 वें संशोधन के लिए परिकल्पित अतिरिक्त कार्य करने के लिए पर्याप्त होंगे।
30. एमएनपीएसपी को अपने मौजूदा प्रणाली में कतिपय छोटे-मोटे सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर आशोधन करने पड़ सकते हैं। उपयुक्त उल्लिखित प्रस्तुतिकरण के दौरान, एक एमएनपीएसपी ने यहां तक उल्लेख किया कि 7 वें संशोधन के लिए अपेक्षित अल्पकालिक परिवर्तनों को स्वयं मौजूदा प्रणाली में किया जाएगा। इसका यह अभिप्राय होगा कि कार्यान्वयन करने के लिए किए जाने वाले अपेक्षित सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर आशोधन कम से कम किए जाने चाहिए। अन्य एमएनपीएसपी ने उल्लेख किया है कि 7 वें संशोधन के कार्यान्वयन के लिए उसे हार्डवेयर घटकों की कुल 4 इकाईयों की आवश्यकता होगी (अर्थात् एक भंडारण इकाई, आईटीएसएम/नेटवर्क और प्रणालीगत निगरानी के लिए एक साधन और एसएमपीपी सर्वरों के लिए दो इकाईयां)। तदनुसार, प्राधिकरण ने पाया कि 7 वें संशोधन के कार्यान्वयन के लिए किया जाने वाले अपेक्षित अतिरिक्त कार्य से एमएनपीएसपी पर कोई अतिरिक्त केपेक्स और ओपेक्स लागत नहीं आएगी।

31. यदि 7वें संशोधन को लागू करने के लिए मौजूदा हार्डवेयर में सीमांत क्षमता का 'ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर' अथवा मौजूदा लाइसेंसप्राप्त सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाए तो इस पर आने वाली लागत चूनतम होनी चाहिए। यदि यह अनुमति दी जाती है कि परिवर्तनों को लागू करने के लिए नए अतिरिक्त हार्डवेयर और अलग से लाइसेंस प्राप्त सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जा सकता है, तो 7वें संशोधन के कार्यान्वयन में शामिल अतिरिक्त कार्य पर कुल 87 लाख रुपए प्रतिवर्ष की लागत आएगी। इसकी गणना करने के लिए, प्राधिकरण ने संबंधित परिचालन व्यय के साथ, कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर विकास/लाइसेंसिंग पर पूँजीगत व्यय को मूल्यहास माना है। प्रतिवर्ष 367 लाख की औसत पोर्टिंग अनुरोध की प्रमात्रा (अर्थात् पिछले तीन वित्तीय वर्षों का औसत) पर विचार करते हुए, प्राधिकरण निर्धारित करता है कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की अतिरिक्त आवश्यकताओं, यदि एमएनपीएसपी द्वारा आवश्यक हो तो, को कवर करने के लिए प्रति पोर्ट 23 पैसे की अतिरिक्त लागत पर्याप्त है। इसमें 7वें संशोधन के तहत एमएनपीएसपी द्वारा यूपीसी अनुरोधों पर कार्यावाही करने के लिए पर्याप्त रूप से लागत कवर होगी। इस प्रकार, एमएनपी विनियम में किए गए 7वें संशोधन के अनुसार पीपीटीसी को समग्र एमएनपी प्रक्रिया को कवर करना होता है, जिसे निम्नानुसार परिकलित किया गया है:

व्योरा	इकाई	राशि
तीन वर्षों के लिए कुल लागत	लाख रुपए में	6011.19
प्राप्त हुए पोर्टिंग अनुरोधों की संख्या	लाख में	1102.08
प्रति पोर्ट ट्रांजेक्शन लागत	रुपए में	5.45
पीपीटीसी का वृद्धिशील घटक	रुपए में	0.23
कुल प्रति पोर्ट ट्रांजेक्शन लागत	रुपए में	5.68
1 प्रतिशत की दर से लाइसेंस शुल्क	रुपए में	0.06
प्रति पोर्ट ट्रांजेक्शन प्रभार	रुपए में	5.74

32. एमएनएसपीएस ने यह भी उल्लेख किया कि प्राधिकरण को वार्षिक आधार की बजाय तीन वर्ष के आधार पर प्रशुल्क की समीक्षा करनी चाहिए क्योंकि इससे व्यवसाय में स्थिरता और निरंतरता प्राप्त होगी। प्राधिकरण ने इस पर विचार किया है और यह नोट किया है कि पीपीटीसी के वृद्धिशील घटक का निर्धारण करने के लिए, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर आवश्यकताओं से संबंधित वास्तविक लागत डॉटा उपलब्ध नहीं है और यह केवल परिवर्तन लागू होने और सामग्री के बिलों के तैयार किए जाने के बाद ही उपलब्ध होंगे। एक एमएनपीएसपी ने यह भी निवेदन किया कि 7 वें संशोधन का अनुपालन करने की लागत के साथ-साथ यूपीसी प्रमात्रा, इसे आरंभ किए जाने के समय पर ज्ञात नहीं होती है। अन्य एमएनपीएसपी ने यह भी उल्लेख किया है कि किसी भी तात्कालिकता की स्थिति में प्रशुल्क की समीक्षा बीच की अवधि में की जा सकती है। वैसे भी, प्राधिकरण ने आवश्यकता होने पर एक वर्ष के बाद पीपीटीसी की समीक्षा करने पर विचार करने का निर्णय लिया है।

अनुषंगी प्रभारों की समीक्षा

33. एमएनपी विनियमों में 7वें संशोधन से पहले परामर्श प्रक्रिया के दौरान, हितधारकों की टिप्पणियों के लिए अनुषंगी सेवा प्रभार का मुद्दा उठाया गया था। हितधारकों की टिप्पणियों की जांच के बाद, प्राधिकरण ने नोट किया कि अनुषंगी सेवा प्रभार का प्रावधान विनियमों में बना रहेगा जो कि प्रभारों की वास्तविक राशि को परिभाषित करने के समय परामर्श के अध्यधीन होगा अन्यथा इसे प्रति पोर्ट लेनदेन प्रभार में सम्मिलित कर लिया जाएगा।
34. तदनुसार, हितधारकों की टिप्पणियां प्राप्त करने के लिए निम्नवत प्रश्न उठाया गया था:
- क्या 'प्रति पोर्ट ट्रांजेक्शन' और 'अनुषंगी सेवाओं' के लिए प्रभारों को अलग से अथवा समेकित प्रभारों के रूप में निर्धारित किया जाना चाहिए। कृपया आपके द्वारा सुझाई गई विधि को अपनाने के लिए तर्क के साथ-साथ, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, अन्य संसाधनों और ऊपरिव्यय आदि की लागत को इगत करते हुए विस्तृत परिकलन के साथ अपनी प्रतिक्रिया का औचित्य सिद्ध करें।
35. हितधारकों को 'प्रति पोर्ट ट्रांजेक्शन प्रभार' और अनुषंगी प्रभारों के नाम से जाने वाले अन्य प्रभारों का निर्धारण करने के लिए नीचे दिए गए दो विकल्पों पर टिप्पणी प्रदान करनी थी:-
- (i) लागत के आधार पर अथवा वैकल्पिक रूप से, 'प्रति पोर्ट ट्रांजेक्शन प्रभार', 'नंबर रिटर्न प्रभार', 'डॉटाबेस डॉउनलोड प्रभार', 'पोर्ट रद्दीकरण प्रभार', 'सब्सक्राइबर पुनर्कनेक्शन प्रभार' और 'मुगातान नहीं किए जाने पर नम्बर बंद करने हेतु प्रभार' के लिए पृथक प्रभार का निर्धारण किया जा सकता है;
 - (ii) केवल एक शुल्क अर्थात् 'प्रति पोर्ट ट्रांजेक्शन प्रभार' को लागू किया जा सकता है और अन्य सभी प्रभारों की लागत जिन्हें 'अनुषंगी प्रभार' कहा गया है को 'प्रति पोर्ट ट्रांजेक्शन प्रभार' में सम्मिलित किया जा सकता है।
36. इस संबंध में, अधिकांश हितधारकों ने उल्लेख किया है कि 'अनुषंगी प्रभारों' के लिए भी प्रभारों को सम्मिलित करते हुए एक समेकित 'प्रति पोर्ट ट्रांजेक्शन प्रभार' होना चाहिए। एक हितधारक ने टिप्पणी की है कि 'नंबर रिटर्न', 'सब्सक्राइबर रिकनेक्शन' और 'नॉन-पेमेंट डिस्कनेक्शन' को पृथक रूप से प्रभारित किया जाना चाहिए, जबकि 'पोर्ट कैंसिलेशन चार्ज' को पीपीटीसी में शामिल किया जाना चाहिए। इसके अलावा, डॉटाबेस डॉउनलोड निःशुल्क प्रदान किया जाएगा। एक एमएनएसपीएस ने बार-बार डॉउनलोड किए जाने से उसके दुरुपयोग से बचने के लिए डॉटाबेस डॉउनलोड के लिए प्रति ऑपरेटर कोटा निर्धारित करने का भी प्रस्ताव रखा।

विश्लेषण

37. नीचे यथा उल्लिखित क्रियाकलापों को करने के लिए दूरसंचार मोबाइल नंबर पोर्टबिलिटी (सातवां संशोधन) विनियम, 2018 में, एमएनपीएसपी को भुगतान किए जाने वाले अनुषंगी सेवा प्रभार का उपबंध विनियम में किया गया है:
- (क) **नंबर रिटर्न चार्ज :** भुगतान न करने सहित किसी भी कारण के बाद नंबर रेज होल्डर को मोबाइल नंबर वापस करने की सुविधा के लिए नंबर रिटर्न चार्ज।
 - (ख) **डॉटाबेस डॉउनलोड प्रभार :** पहुंच सेवा प्रदाता द्वारा नंबर पोर्टबिलिटी डॉटाबेस डाउनलोड करने के लिए डॉटाबेस डॉउनलोड प्रभार।
 - (ग) **पोर्ट रद्दीकरण प्रभार:** प्रदाता प्रचालक के सब्सक्राइबर के 'पोर्ट वापसी' के अनुरोध के निष्पादन के लिए पोर्ट रद्दीकरण प्रभार।
 - (घ) **सब्सक्राइबर रिकनेक्शन प्रभार :** अपने नेटवर्क में प्राप्तकर्ता ऑपरेटर के पोर्ट किए गए सब्सक्राइबर को पुनः जोड़ने की सुविधा के लिए सब्सक्राइबर रिकनेक्शन प्रभार।
 - (ङ) **नॉन-पेमेंट डिस्कनेक्शन प्रभार :** ऐसे पोस्टपेड सब्सक्राइबर जिन्होंने अपना नंबर पोर्ट कराने के पश्चात् प्रदाता ऑपरेटर का बकाया नहीं चुकाया है उनके मोबाइल नंबर को बंद करने को सुकर बनाना।
38. अनुषंगी सेवाओं के लिए पृथक प्रभारों के संबंध में, यह नोट किया जाता है कि पीपीटीसी को 'लागत-प्लस' के आधार पर निर्धारित किया गया है। इसका अभियांत्र यह है कि एमएनपीएसपी द्वारा इसकी सभी सेवाओं को प्रदान करने में एमएनपीएसपी की सभी लागतों का पीपीटीसी को परिकलित करते हुए ध्यान में रखा गया है। यह नोट किया जा सकता है कि एमएनपी विनियमों के 7 वें संशोधन में यथा सूचीबद्ध अनुषंगी सेवाएं, पहले से ही एमएनपीएसपी द्वारा उपलब्ध कराई जा रही हैं जैसा कि नीचे तालिका में दिया गया है:

तालिका: जनवरी से दिसम्बर, 2018 के अवधि के लिए अनुषंगी क्रियाकलापों के बारे में जानकारी

एमएनपी अंचल	प्राप्त हुए वापसी के अनुरोधों की संख्या	डॉटाबेस डॉउनलोड की कुल संख्या	प्राप्त हुए पोर्ट रद्दीकरण के अनुरोधों की संख्या	प्राप्त हुए सब्सक्राइबर रिकनेक्शन अनुरोधों की संख्या	प्राप्त हुए एनपीडी अनुरोधों की संख्या
अंचल I	9351497	954	107517	787266	1620505
अंचल II	7691841	1499	14972	शून्य ¹	480104
कुल	17043338	2453	122489	787266	2100609
प्रतिमाह औसत	1420278	204	10207	65606	175051

39. प्राधिकरण ने पीपीटीसी का निर्धारण करने के लिए 'कॉस्ट प्लस' पद्धति का उपयोग किया है। वैसे भी, पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए सेवाएं प्रदान करने में आने वाली कुल लागतों को ध्यान में रखते हुए, अनुषंगी सेवाएं प्रदान करने हेतु लागतों भी शामिल की गई हैं। पिछले तीन वित्तीय वर्षों की लागतों को ध्यान में रखते हुए, एमएनपीएसपी द्वारा किए गए किसी भी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर परिवर्तनों की लागतों पर भी विचार किया गया है। इसलिए, प्राधिकरण यह निर्धारित करता है कि 'अनुषंगी सेवाएं प्रदान करने के लिए अलग-अलग शुल्क आवश्यक नहीं हैं क्योंकि पीपीटीसी का परिकलन करने के लिए सभी सेवाओं को प्रदान करने के लिए लागत पर विचार किया गया है। इसके अलावा, डॉटाबेस डॉउनलोड की वर्तमान प्रमात्रा को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकरण ने निर्णय लिया कि टीएसपी द्वारा डॉटाबेस डॉउनलोड के लिए कोई कोटा निर्धारित करने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा, डॉटाबेस डॉउनलोड की वर्तमान प्रमात्रा को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकरण ने निर्णय लिया कि टीएसपी द्वारा डॉटाबेस डॉउनलोड के लिए कोई कोटा निर्धारित करने की आवश्यकता नहीं है।

डिपिंग प्रभारों की समीक्षा

40. हितधारकों की टिप्पणियां प्राप्त करने के लिए निम्नवत प्रश्न उठाया गया था:
- क्या डिपिंग प्रभार, जो वर्तमान में 'फारबीयरेंस' के तहत है, की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता है? यदि हाँ, तो डिपिंग प्रभारों की दरें निर्धारित करने के लिए पद्धति का सुझाव दें। अपनी प्रतिक्रिया का औचित्य के साथ समर्थन करें।
41. अधिकांश हितधारकों ने टिप्पणी की है कि डिपिंग प्रभार 'फारबीयरेंस' के तहत जारी रहने चाहिए और कोई भी सेवा प्रदाता जिसे एमएनपीएसपी के तहत डिपिंग सेवाओं की आवश्यकता होती है, वह एमएनपीएसपी के साथ पारस्परिक रूप से सहमत शर्तों पर इसका लाभ उठा सकता है। एक हितधारक ने टिप्पणी की है कि आज तक, किसी भी ऑपरेटर ने इस सेवा का उपयोग नहीं किया है और इसलिए, एमएनपीएसपी को अतिरिक्त लागत संबंधित अवसरचना को हटाने की अनुमति दी जानी चाहिए।
42. विभिन्न हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियों और प्रति टिप्पणियों का विश्लेषण करने के पश्चात् प्राधिकरण निर्णय लेता है कि डिपिंग प्रभार 'फारबीयरेंस' के तहत जारी रहेंगे। एमएनपीएसपी और पहुंच प्रदाता अथवा आईएलडीओ, जो एमएनपीएसपी की पूछताछ प्रतिक्रिया प्रणाली का उपयोग करने का इच्छुक हो, उन दोनों के द्वारा डिपिंग चार्ज को पारस्परिक रूप से निर्धारित किया जा सकता है।

¹ अंचल II ने प्राप्त किए गए 'सब्सक्राइबर रिकनेक्शन अनुरोधों' के संबंध में कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं कराए हैं।

उपभोक्ताओं द्वारा भुगतान किए जाने वाले पोर्टिंग प्रभार की समीक्षा

43. एमएनपी प्रभारों संबंधी विनियमों में यथा उपबंधित, दूरसंचार प्रशुल्क (उनचासवां संशोधन) आदेश, 2009 में प्रति पोर्ट ट्रांजेक्शन प्रभार को प्रशुल्क की अधिकतम सीमा के रूप में विहित किया गया था, जिसे प्राप्तकर्ता ऑपरेटर द्वारा सब्सक्राइबरों से प्रभारित किया जा सकता है। तदनुसार, हितधारकों की टिप्पणियों के लिए निम्नलिखित प्रश्न उठाया गया था:
- व्या सब्सक्राइबर द्वारा प्राप्तकर्ता प्रचालक को भुगतान किए जाने वाले पोर्टिंग प्रभार, वर्तमान व्यवस्था के अनुसार अधिकतम प्रभार के रूप में निर्धारित किए जाते रहने चाहिए? यदि नहीं, तो कृपया सब्सक्राइबर द्वारा पोर्टिंग प्रभार के परिकलन के लिए पद्धति और ध्यान दिए जाने वाले विभिन्न बिंदु सुझाएं।
44. लगभग सभी हितधारकों ने मौजूदा पद्धति को जारी रखने का सुझाव दिया है। इस संबंध में, एक हितधारक ने टिप्पणी की है कि दूरसंचार बाजार में अधिक प्रतिस्पर्धा के कारण, पोर्टिंग प्रभार, जिसे उपभोक्ता द्वारा पोर्टिंग अनुरोध का सृजन करने के लिए भुगतान किया जाता है, प्राप्तकर्ता ऑपरेटरों द्वारा अवशोषित किया जा रहा है।
45. एक अन्य हितधारक ने टिप्पणी की कि हाल ही में कुछ टीएसपी के बंद होने और क्षेत्र में चल रहे समेकन के कारण, सब्सक्राइबरों को मजबूर होकर पोर्टिंग का सहारा लेना पड़ रहा है और इसलिए, सब्सक्राइबरों के हित में, जबरन की जाने वाली पोर्टिंग के लिए कोई शुल्क देय नहीं होना चाहिए।
46. वर्तमान मुद्दों का विश्लेषण करने के बाद, प्राधिकरण यह निर्धारित करता है कि प्रति पोर्ट ट्रांजेक्शन प्रभारों की मौजूदा पद्धति सब्सक्राइबरों द्वारा प्राप्तकर्ता ऑपरेटर को भुगतान किए जाने वाले पोर्टिंग प्रभारों की अधिकतम सीमा बनी रहेगी।
- मसौदा विनियमों को जारी किए जाने के उपरांत हितधारकों द्वारा उठाए गए मुद्दे**
47. हितधारकों ने मुख्यतः विभिन्न मुद्दों पर अपने पिछली टिप्पणियों को ही दोहराया है। कतिपय नई टिप्पणियों को भी प्रस्तुत किया गया है। उठाए गए विभिन्न मुद्दे और इस पर किया गया विचार– विमर्श निम्नानुसार है:
- 47.1 एक एमएनएसपी ने यह उल्लेख किया कि मौजूदा प्रचालनों के लिए कुल चालू लागतों पर चर्चा करते हुए और साथ ही सातवें संशोधन के तहत परिकल्पित परिवर्तनों पर निर्णय लेते हुए, उपयुक्त हितधारक एमएनपीएसपी हैं न कि दूरसंचार सेवा प्रदाता, जिनके पास लागत को तो एक ओर छोड़िए, तकनीकी रूप से, एमएनपीएसपी द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं में शामिल जटिल तथा कठिन प्रक्रिया का मूल्यांकन करने और/अथवा टिप्पणियां करने के लिए तकनीकी ज्ञान का अभाव है। प्राधिकरण उक्त एमएनपीएसपी द्वारा अपनाए गए रूख से असहमत है क्योंकि टीएसपी इस समग्र परामर्श प्रक्रिया के समान रूप से महत्वपूर्ण हितधारक हैं। इसके अलावा, एमएनपीएसपी को अब सौंपे गए प्राथमिक अतिरिक्त कार्य अर्थात् यूपीसी सृजन करने का कार्य, को वर्तमान में टीएसपी द्वारा ही किया जा रहा है। किसी भी स्थिति में, टीएसपी से पूछना सर्वथा उचित होगा कि वे उस मूल्य के संबंध में अपनी टिप्पणियां दें जिसका भुगतान उनके द्वारा किया जाना है। परामर्श प्रक्रिया का मूलभूत आधार मुद्दे से प्रभावित होने वाले पृथक हितधारकों से टिप्पणियां प्राप्त करना है।
- 47.2 टीएसपी ने दोहराया है कि रॉयलटी/परामर्श/लाइसेंसिंग की लागत की शाश्वत रूप से वसूली नहीं की जा सकती है चूंकि एमएनपीएसपी ने पिछले 8 से 9 वर्षों के दौरान पर्याप्त विशेषज्ञता हासिल की है। तदनुसार, टीएसपी ने प्राधिकरण से पीपीटीसी के परिकलन करने के लिए इन लागतों को अलग रखने का अनुरोध किया है और केवल सेवा सृजन/सेवा प्रदान किए जाने की लागत को ही सम्मिलित किए जाने का अनुरोध किया है जैसे हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, प्रचालन तथा रखरखाव। तथापि प्राधिकरण ने एमएनपीएसपी के वार्षिक लेखा में उपलब्ध ऐतिहासिक लेखा परीक्षित लागत घटक पर विचार करने का निर्णय लिया है।
- 47.3 एमएनपीएसपी ने यह भी दोहराया है कि अशोध्य ऋण को वहन करने की लागत, वास्तविक लागत है और इन्हें समग्र लागतों में सम्मिलित किया जाना चाहिए। एमएनपीएसपी का यह मत है कि विभिन्न टीएसपी द्वारा देयताओं का भुगतान नहीं किया जाना उनके समग्र वित्तीय स्थिति को प्रभावित कर रहा है। इस संबंध में, प्राधिकरण नोट करता है कि एमएनपी विनियमों के विनियम 15 के अनुसार, प्राप्तकर्ता आपरेटर (आरओ) को बिल की गई पीपीटीसी राशि को एमएनपीएसपी को बिल की प्राप्ति के पंद्रह दिनों अथवा ऐसी समय सीमा के भीतर भुगतान करना अपेक्षित होता है जिस पर वे आपस में सहमत हों। यदि आरओ इन विनियमों का पालन नहीं करते हैं, तो यह दोनों सेवा प्रदाताओं के बीच विवाद हो जाता है तथा उपयुक्त समाधान प्राप्त करने के लिए दोनों में से कोई भी पक्ष माननीय दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय प्राधिकरण (टीडीएसएटी) जा सकता है। इसलिए, प्राधिकरण का मत है कि पीपीटीसी का परिकलन करते हुए अशोध्य ऋण को लागत घटक नहीं माना जा सकता है।
- 47.4 एक एमएनपीएसपी ने यह भी सुझाव दिया है कि टीएसपी द्वारा एमएनपीएसपी को देर से भुगतान करने पर भारी जुर्माना लगाया जाना चाहिए ताकि अशोध्य ऋण का प्रभाव कम से कम हो। प्राधिकरण ने उक्त एमएनपीएसपी के सुझाव पर सावधानीपूर्वक विचार किया है तथा उसका मत है कि इसे मुख्य रूप से दो कारणों से स्वीकार नहीं किया जा सकता है अर्थात् सर्वप्रथम् भुगतान न करने अथवा विलंब से भुगतान के लिए जुर्माना लगाना वर्तमान परामर्श के दायरे से बाहर है क्योंकि इन्हें एमएनपी प्रभार संबंधी विनियमों के तहत प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जा सकता है, दूसरे जैसा कि पहले से ही पिछले पैरा में उल्लेख किया गया है, माननीय टीडीएसएट में समाधान के लिए आवेदन करते समय, हमेशा टीएसपी द्वारा गैर-भुगतान अथवा विलंब से विचार किया जाने वाले भुगतान के लिए उपयुक्त उपाय कर सकते हैं। एक अन्य एमएनपीएसपी ने सुझाव दिया कि एमएनपीएसपी को चूककर्ता टीएसपी को एमएनपी सेवाएं उपलब्ध कराने से वंचित करना चाहिए। प्राधिकरण ने इस सुझाव पर विचार किया है और पुनः वह इसे दो मुख्य कारणों से स्वीकार नहीं कर सकता है अर्थात् सर्वप्रथम् एमएनपीएसपी को चूककर्ता टीएसपी को एमएनपी सेवाएं उपलब्ध कराने से वंचित करना, वर्तमान परामर्श प्रक्रिया के क्षत्राधिकार से इतर है, दूसरे और अधिक महत्वपूर्ण कारण यह है कि यह इच्छुक सब्सक्राइबर के हितों को क्षति पहुंचाएगा जो उक्त टीएसपी को अपना नम्बर पोर्ट करना चाहते हैं।
- 47.5 एमएनपीएसपी ने आगे यह निवेदन किया है कि 6011.19 लाख रुपए की कुल लागत का विस्तृत व्योरा मसौदा विनियमों में उपलब्ध नहीं कराया गया था। यह इस बात को जानने के लिए अनिवार्य है कि पीपीटीसी का परिकलन करने के लिए किन लागतों को शामिल नहीं किया गया है।

एक एमएनपीएसपी ने उल्लेख किया कि पारदर्शिता के महेनजर, प्राधिकरण द्वारा विचार किए जाने वाले लागत ब्योरे को एमएनपीएसपी के साथ साझा किया जाना चाहिए ताकि वे अनुमन्य और / अथवा अस्वीकृत की लागतों से अवगत हो सकें। तथापि, यह देखा गया है कि खुला मंच चर्चा के दौरान उक्त एमएनपीएसपी ने दावा किया है कि कुछ लागतें हैं जिन्हें साझा किया जा सकता है और कुछ लागतें ऐसी हैं जिन्हें इस तथ्य के कारण सार्वजनिक रूप से साझा नहीं किया जा सकता कि वे ऐसी लागतें हैं जो उनके लिए व्यावसायिक रूप से प्रतिस्पर्द्धी हैं और इससे अन्य देशों में बोली लगाने हेतु उनकी मूल कंपनियां बाधित होंगी।

- 47.6 उक्त एमएनपीएसपी ने यह भी कहा है कि कई अभ्यावेदनों के बावजूद, प्राधिकरण ने वास्तविक लागतों को नकारात्मक और अनौचित्यपूर्ण तरीके से अस्वीकृत कर दिया है। इसने यह भी सिफारिश की है कि प्राधिकरण को एक तुतीय- पक्ष अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार नियुक्त करना चाहिए, जिसके पास लागतों, पोर्टिंग 'वॉल्यूम' और परिणामी प्रशुल्क की समीक्षा करने और निर्धारण करने के लिए क्षेत्रगत विशेषज्ञता हो। इस संबंध में इस बात को पुनः दोहराया जाता है कि प्राधिकरण ने एमएनपीएसपी के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के माध्यम से उपलब्ध कुल लागतों पर विचार किया है, जिसमें कृतिपय अपवाद जैसे अशोध्य ऋण/अशोध्य ऋण हेतु व्यवस्था, मुद्रा में उतार-चढ़ाव से होने वाले नुकसान शामिल हैं (इसके लिए पर्याप्त रूप से विस्तृत व्योरा दिया गया है)। इसके अलावा, प्राधिकरण ने पीपीटीसी का निर्धारण करने के लिए दो एमएनपीएसपी में से अधिक किफायती एमएनपीएसपी की कुल लागत पर विचार किया है (जिसमें रॉयल्टी/लाइसेंस शुल्क तथा मूल्यद्वास शामिल हैं, जैसा कि लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों में दर्शाया गया है।) दूसरे शब्दों में, पीपीटीसी का निर्धारण करने के लिए एमएनपीएसपी की कुल लागत तथा पोर्ट 'वॉल्यूम' डॉटा सहित निम्न प्रति पोर्ट ट्रांसेक्शन लागत पर विचार किया गया है।
- 47.7 व्याख्यात्मक ज्ञापन में लागतों के विस्तृत ब्योरे (6011.19 लाख रुपए) को दर्शाने वाली एक संशोधित तालिका भी जोड़ी गई है। यह अधिक उपयुक्त होगा यदि एमएनपीएसपी अपनी लागत संरचना की समीक्षा करें और लागत दक्षता प्राप्त करने के लिए सुधार किए जाने वाले क्षेत्रों की पहचान करें।
- 47.8 एमएनपीएसपी ने फिर से यह दावा किया है कि नियोजित पूँजी पर लाभ 15 प्रतिशत की दर से पर्याप्त नहीं है और इसे करें के भुगतान के बाद मापा जाना चाहिए ताकि नियोजित पूँजी पर पर्याप्त लाभ प्रदान किया जा सके। एक एमएनपीएसपी ने 25 प्रतिशत की दर से लागत में वृद्धि करने का सुझाव दिया है। इस मुद्रे का पहले से ही मसौदा विनियमों में पर्याप्त रूप से समाधान किया गया और व्याख्यात्मक ज्ञापन में विस्तृत से स्पष्ट किया गया है। प्राधिकरण ने दोहराया कि एमएनपीएसपी ने रोस (आरओसीई) की दर पर पुनर्विचार करने के लिए कोई बाध्यकारी कारण उपलब्ध नहीं कराया है। इसलिए, मौजूदा पद्धति के अनुसार, कुल लागत का निर्धारण करने के लिए नियोजित की गई पूँजी पर 15 प्रतिशत की दर से लाभ प्रदान करने पर विचार किया गया है। एक अन्य एमएनपीएसपी ने नियोजित की गई पूँजी की गणना का आधार उपलब्ध कराने का सुझाव दिया है। तदनुसार, यह स्पष्ट किया जाता है कि नियोजित पूँजी की गणना अचल संपत्तियों के शुद्ध बही मूल्य, चल रहे कुल पूँजीगत कार्यों और वित्तीय वर्ष के अंत में शुद्ध कार्यशील पूँजी के रूप में की गई है।
- 47.9 एमएनपीएसपी ने आगे निवेदन किया है कि पीपीटीसी में कमी से सहायक सेवाएं निःशुल्क प्रदान की जाएंगी। इसके अलावा, डॉटाबेस डॉउनलोड की दर प्रति माह दो निःशुल्क डॉउनलोड के पश्चात 15000/- रुपए की दर से निर्धारित की जानी चाहिए। इस संबंध में, प्राधिकरण ने पाया है कि संबंधित एमएनपीएसपी ने विरोधाभासी टिप्पणियां की हैं। वहीं दूसरी ओर, उक्त एमएनपीएसपी ने यह स्वीकार किया कि इन सेवाओं की लागतें पहले से ही विगत की लागतों में शामिल थीं, जबकि दूसरी ओर, यह दावा किया गया कि पीपीटीसी में कमी से प्रभावी रूप से ऐसी सेवाएं निःशुल्क में प्रदान की जाएंगी। यह कथन सत्य नहीं है, क्योंकि प्राधिकरण ने पीपीटीसी का निर्धारण करने के लिए एमएनपीएसपी द्वारा वहन की गई सभी संगत लागतों पर विचार किया है (पूर्व में स्पष्ट किए गए कृतिपय शीर्ष के अलावा) जिसमें 'अनुभंगी' सेवाएं उपलब्ध कराने की लागतें शामिल हैं। इसलिए, प्राधिकरण इस संबंध में मसौदा विनियमों को बदलने का कोई कारण नहीं पाता है।
- 47.10 एमएनपीएसपी द्वारा यह भी दावा किया गया कि प्राधिकरण ने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर विकास के लिए पूँजीगत लागत की पूर्णतः अनदेखी करते हुए सातवें संशोधन की लागत के रूप में 87 लाख रुपए की लागत के आंकड़े को मनमाने ढंग से लिया है। एमएनपीएसपी ने आगे यह भी दावा किया है कि प्राधिकरण ने एमएनपीएसपी द्वारा केपेक्स और ओपेक्स में पर्याप्त वृद्धि किए जाने संबंधी अपेक्षा के पीछे तर्क नहीं दिया है। वहीं दूसरी ओर, कुछ टीएसपी का यह मत है कि अतिरिक्त लागत/निवेदन एमएनपीएसपी की मौजूदा लागतों का 1 से 3 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। एक टीएसपी ने सुझाव दिया है कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के साथ यह लागत 87 लाख से घटकर 25 प्रतिशत रह जाएगी। सातवें संशोधन के कार्यान्वयन के लिए पीपीटीसी के वृद्धिशील घटक की गणना के औचित्य और आधार का मसौदा विनियम में विस्तार से उल्लेख किया गया था। इस संबंध में, यह दोहराया जाता है कि 7 वें संशोधन के परिणामस्वरूप किया जाने वाला अतिरिक्त कार्य काफी हद तक बिना किसी अथवा न्यूनतम मानव हस्तक्षेप के साथ स्वचालित होगा और मौजूदा प्रचालनों में एमएनपीएसपी द्वारा तैनात मौजूदा कर्मचारी 7 वें संशोधन के तहत किए गए अतिरिक्त कार्य को पूरा करने के लिए पर्याप्त होंगे। जैसा कि ऊपर विस्तार से बताया गया है, 7 वें संशोधन के कार्यान्वयन के लिए शामिल किए गए अतिरिक्त कार्य के लिए पीपीटीसी के वृद्धिशील घटक का निर्धारण करने के लिए एमएनपीएसपी ओर टीएसपी (जो वर्तमान में यूपीसी सूजन और संबद्ध प्रक्रियाओं में लगे हुए हैं) सहित हितधारकों द्वारा प्रदान किए गए डॉटा का उपयोग किया गया है। इसके अलावा, संबंधित एमएनपीएसपी की इन धारणाओं के संबंध में कि वास्तविक आंकड़ों पर विचार नहीं किया गया है, यह उल्लेखनीय है कि एमएनपीएसपी में से किसी ने भी 7 वें संशोधन के लिए परिकल्पित अतिरिक्त कार्य से संबंधित वास्तविक व्यय (सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर संबंधी आवश्यकताओं) से जुड़े आंकड़े उपलब्ध नहीं कराए हैं। इसलिए, प्राधिकरण ने एक वर्ष पश्चात, विगत के लेखापरीक्षित आंकड़े उपलब्ध होने पर पीपीटीसी और अन्य प्रभारों की समीक्षा करने का निर्णय लिया है।
- 47.11 एक एमएनपीएसपी ने यह उल्लेख किया कि प्राधिकरण ने पीपीटीसी से यूपीसी सूजन हेतु पृथक प्रभारों की आवश्यकता पर विचार नहीं किया है। यह भी निवेदन किया गया है कि यूपीसी सूजन तथा एसएमएस को सासाधित करने के अलावा, सातवें संशोधन के तहत पोर्टिंग प्रक्रिया हेतु कृतिपय अन्य परिवर्तन भी हैं, जो लागतों में भी वृद्धि करेंगे और उन पर विचार नहीं किया गया है (उदाहरण के लिए गैर- भुगतान और पुनः कनेक्शन करना)। इस संबंध में, यह नोट किया जाता है कि मसौदा विनियमों में यथा प्रस्तावित पीपीटीसी के वृद्धिशील घटक की गणना, यूपीसी अनुरोधों को संभालने सहित 7 वें संशोधन के कार्यान्वयन से जुड़े सभी अतिरिक्त कार्यों की अनुमानित लागत को कवर करती है और इसलिए, इन विनियमों के तहत पीपीटीसी के संशोधित प्रशुल्क पर्याप्त रूप से 7 वें संशोधन के तहत एमएनपीएसपी द्वारा वहन किए जाने वाले इन व्यय को

- पर्याप्त रूप से सम्मिलित करता है। किसी भी स्थिति में, प्राधिकरण ने एक वर्ष पश्चात्, विगत के लेखापरीक्षित आंकड़े उपलब्ध होने पर पीपीटीसी की समीक्षा करने का निर्णय लिया है।
- 47.12 एक एमएनपीएसपी ने टिप्पणी की है कि पोर्टिंग राजस्व में हुई महत्वपूर्ण कमी को देखते हुए, प्राधिकरण को एमएनपीएसपी को दोनों एमएनपी क्षेत्रों से डॉटा प्राप्त करने में सक्षम बनाना चाहिए और एमएनपीएसपी और तृतीय पक्षों के बीच पारस्परिक रूप से सहमत हुई व्यावसायिक शर्तों के तहत तृतीय पक्षों को डिपिंग सेवाएं प्रदान करनी चाहिए। उक्त एमएनपीएसपी ने कहा है कि इससे एमएनपीएसपी को अनेक सेवाओं में कुछ परिसंपत्तियों और संसाधनों को साझा करने की अनुमति मिल सकती है। जबकि, एमएनपीएसपी की लागत में बदलाव नहीं होगा, उनमें से कुछ भाग को डिपिंग के लिए आवश्यित कर उन लागतों को कम किया जा सकता है। इस संबंध में, प्राधिकरण यह निर्धारित करता है कि डिपिंग प्रभारों से संबंधित प्रश्नुल्क 'फारबीयरेस' के तहत है और एमएनपीएसपी द्वारा उठाया गया मौजूदा मुद्दा इस परामर्श प्रक्रिया के दायरे से बाहर है।
- 47.13 एक एमएनपीएसपी ने दिनांक 01 जनवरी, 2020 तक नए पीपीटीसी प्रश्नुल्क के कार्यान्वयन को विलम्बित करने का अनुरोध किया है। आगे यह अनुरोध किया गया कि है कि सभी हितधारकों द्वारा सातवें संशोधन के कार्यान्वयन के पश्चात् माह की प्रथम तिथि से नए प्रश्नुल्क कार्यान्वित किए जाने चाहिए। प्राधिकरण ने एमएनपीएसपी को दौरान प्रश्नुल्क में परिवर्तन किए जाने के फलस्वरूप विलिंग प्रणाली में सामना की जा रही समस्या पर विचार किया। तथापि, प्राधिकरण यह निर्धारित करता है कि संशोधित प्रश्नुल्क विशिष्ट रूप से सातवें संशोधन के कार्यान्वयन हेतु वृद्धिकारक घटक को कवर करता है और इसलिए, सातवां संशोधन और संशोधित प्रश्नुल्क एक साथ लागू होने चाहिए। एमएनपीएसपी द्वारा व्यक्त की गई समस्या का उनकी विलिंग प्रणाली में सुगमता से समाधान किया जाना चाहिए।
- 47.14 एक टीएसपी ने दिनांक 31 जनवरी, 2018 (अर्थात् जब एमएनपी प्रभार संबंधी विनियमों में पिछले संशोधन को अविस्पृचित किया गया था) से लेकर माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा उक्त संशोधन को समाप्त किए जाने के पश्चात् मौजूदा संशोधन लागू होने की तिथि के दौरान लागू पीपीटीसी दर के संबंध में प्राधिकरण से स्पष्टीकरण मांगा है। इस संबंध में प्राधिकरण का यह मत है कि पक्षकारों के दावे तथा देयताएं माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 08 मार्च, 2019 के आदेश के माध्यम से दिए गए निष्कर्ष/की गई टिप्पणियों पर निर्भर करेगा। पक्षकारों द्वारा किसी मुद्दे पर मतान्तर होने के कारण, किसी भी प्रकार के विवाद होने की स्थिति में क्षुब्ध पक्ष अपनी शिकायतों के समाधान के लिए उपयुक्त मंच पर जा सकता है।
- 47.15 टीएसपी ने प्राधिकरण से दोनों एमएनपीएसपी के लिए समग्र 22 सेवा क्षेत्रों को खोलकर एमएनपीएसपी का चयन करने में टीएसपी के साथ-साथ स्बस्क्राइबरों के लिए विकल्प नहीं होने की स्थिति को समाप्त कर एमएनपी सेवाओं में प्रतिस्पर्धा के मुद्दे का समाधान करने का अनुरोध भी किया। अन्य हितधारक ने अधिक कुशल प्रक्रियाओं का सूजन करने तथा प्रचालन की लागत को कम करने के लिए 'ब्लॉकचेन' को अपनाने की वकालत की है। प्राधिकरण ने इन टिप्पणियों पर विचार किया है तथा वह इस बात से सहमत है कि एमएनपी सेवाओं में प्रतिस्पर्धा का संवर्धन करने से एमएनपी सेवाओं में कुशलता तथा नवोन्मेष में सुधार होगा। तथापि, इन सुझावों का मौजूदा परामर्श प्रक्रिया में समाधान नहीं किया जा सकता है। प्राधिकरण सामान्य रूप से दूरसंचार सेवाओं तथा विशिष्ट रूप से एमएनपी सेवाओं में प्रतिस्पर्धा को सुकर बनाने तथा कुशलता को बढ़ावा देने के लिए उपाय करता रहेगा।
- 47.16 एमएनपीएसपी ने निवेदन किया है कि पीपीटीसी का परिकलन करने के लिए प्राधिकरण द्वारा विचार किए जाने वाले पोर्ट 'वॉल्यूम', मौजूदा 'वॉल्यूम' अथवा भविष्य के लिए परिकलित 'वॉल्यूम' को नहीं दर्शाते हैं, जिसपर पीपीटीसी लागू होंगे। एमएनपीएसपी ने टीएसपी द्वारा प्रचालनों को बंद किए जाने/उनके विलय के परिणामस्वरूप एक बार होने वाले चढ़ाव हेतु पोर्ट परिमाण को सामान्य बनाने के दावे को दोहराया है। एक एमएनपीएसपी ने पीपीटीसी का परिकलन करने के लिए उच्च अथवा कम संख्या का उपयोग करने हेतु जोखिम को कम से कम करने के लिए चरणबद्ध मूल्यनिर्धारण ढांचे का भी सुझाव दिया है।
- 47.17 प्राधिकरण ने टीयर्ड मूल ढांचे के बारे में दिये गये सुझावों की जांच की है। ऐसी पद्धति में अनेक सापेक्ष अवधारणाओं का समावेश करना पड़ेगा तथा दोनों एमएनपीएसपी तथा टीएसपी के लिए लागू करने में दुरुहोगा। अतः यह व्यवहारिक विकल्प नहीं होगा। प्राधिकरण ने एमएनपीएसपी के दूसरे निवेदन पर विचार किया तथा यह निर्णय किया कि एक बार की अपवादी पोर्टिंग, जो कि टीएसपी के बंद या एक होने से हुई है उसे पोर्टिंग मात्राओं के आकलन हेतु लिए जाना चाहिए जिससे कि वे ऐसी फोर्सड पोर्टिंग के अभाव में होने वाली सामान्य पोर्टिंग का उच्चत प्रदर्शन करें। मुख्य सेवा प्रदाताओं के बीच का बाजार कुछ हद तक स्थिर हो चुका है तथा टीएसपी के बंद या एक होने के कारण होने वाली असामान्य वृद्धि निकट भविष्य में होने की संभावना कम है। अतः पीपीटीसी निर्धारित करने में पोर्टिंग मात्रा के अत्यधिक महत्वपूर्ण होने के कारण यह आवश्यक है कि विचाराधीन पोर्टिंग मात्रा जितनी सामान्य हो सकती है उतनी ही। अतः प्राधिकरण ने पोर्टिंग मात्राओं को विनियमों के मसौदे में उस सीमा तक सामान्य किया था कि उन वर्षों में तीन वर्षों का औसत लेकर वृद्धियों को सामान्य किया जाय। तथापि पोर्टिंग मात्राओं में मौजूदा रुझान फोर्सड पोर्टिंग को हटाने के बाद पोर्टिंग मात्राओं के अधिक सदृश्य दिखते हैं। यह विशेषकर उसके लिए उपयुक्त प्रतीत होता है क्योंकि संबंधित उपयुक्त जानकारी/डाटा प्राधिकरण के पास उपलब्ध है।
- 47.18 दोनों एमएनपीएसपी के बंद होने/एक बार की वृद्धि के अपने अनुमान दिए हैं। उपयुक्त एमएनपीएसपी ने 190.76 लाख पोर्ट को असामान्य अर्थात् उक्त समयावधि में टीएसपी के बंद या एक होने के कारण, इस आधार पर बताया है कि वृद्धियों समान रुझानों से अधिक थी। लेकिन पोर्टिंग में हुई सभी वृद्धियों के टीएसपी के बंद होने या एक होने के कारण फोर्सड पोर्टिंग मान लेना जटित नहीं होगा। भारत में 95 प्रतिशत से अधिक मोबाइल उपभोक्ता ग्रीफेड कनेक्शन हैं जिसके एकार्टन में प्रायः कुछ राशि बची रहती है इसे उपभोक्ता पोर्टिंग के पहले सदैव इस्तेमाल करना चाहेगा। इसके अलावा इनमें से कुछ पोर्ट अनुरोध टीएसपी के बंद या एक होने से मिन्न दूसरे कारणों से हुए होंगे जैसे कि सेवा की घटिया गुणवत्ता, दूसरे टीएसपी के द्वारा दी गई बेहतर टैरिफ दरें/सेवायें इत्यादि। अतः प्राधिकरण ने यह निर्णय किया है कि वह फोर्सड पोर्टिंग मात्रा का आकलन तुलनात्मक रूप से अधिक वस्तुगत मानक के उपयोग द्वारा करेगा जिसे एमएनपीएसपी और टीएसपी द्वारा संबंधित महिनों में प्राधिकरण को दी गई सूचना के आधार पर किया जायेगा। टीएसपी ने संबंधित लाईसेंस सर्विस एरिया में अपनी गतिविधियों के बंद होने/एक होने के तिथियों की सूचना प्राधिकरण को दी है। एमएनपीएसपी ने भी प्राधिकरण को स्वतंत्र रूप से टीएसपी-वार तथा लाईसेंस सर्विस एरिया में गतिविधियों के बंद होने/एक होने के तिथियों की सूचना दी है। अतः प्राधिकरण ने यह निर्णय लिया है कि संबंधित लाईसेंस सर्विस एरिया में टीएसपी की सेवा के बंद होने से लेकर (जैसा कि प्राधिकरण को रिपोर्ट किया गया है) जिस महिने तक प्राधिकरण ने टीएसपी तथा

एमएनपीएसपी को उपभोक्ता पोर्टिंग को पूरा करने का निर्देश दिया था, बंद/एक होने वाले टीएसपी की पोर्ट आउट मात्राओं को फोर्सड पोर्टिंग माना जायेगा और पोर्टिंग मात्राओं को उस सीमा तक सामान्यकृत किया जायेगा।

47.19 उपर्युक्त मानदंड पर विचार करने के बाद यह पाया जाता है कि मसौदा विनियमों में प्राधिकरण द्वारा उपर्युक्त एमएनपीएसपी के लिए विचारित कुल पोर्ट मात्रा 1102.08 लाख में से 120.60 लाख पोर्ट मात्रा टीएसपी के बंद/एक होने के कारण हुई एक बार की वृद्धि के कारण है। अतः उपर्युक्त एमएनपीएसपी के लिए सामान्यकृत पोर्ट मात्रा 981.48 लाख है (अन्य शब्दों में 327.16 लाख एक साल में)। सामान्यकृत पोर्ट मात्रा को वर्तमान पोर्टिंग मात्रा (प्राधिकरण ने जनवरी से जुलाई, 2019 की पोर्ट मात्रा, जो अब उपलब्ध है) से तुलना करने पर यह उल्लेखनीय है कि जनवरी, 2019 से हो रही पोर्टिंग मात्रा को वार्षिक आधार पर आंकित करने पर उपर्युक्त एमएनपीएसपी की पोर्ट मात्रा 313 लाख होगी। अतः प्राधिकरण द्वारा आंकित सामान्यकृत पोर्ट मात्रा मौजूदा पोर्ट मात्रा की रुक्झान को उचित रूप से प्रदर्शित करती है।

47.20 उपर्युक्त के आधार पर पीपीटीसी का संशोधित गणना निम्नलिखित है:

क्रम सं.	ब्यौरा	इकाई	राशि
क	तीन वर्षों के लिए कुल लागत	लाख रुपए में	6011.19
ख	तीन वर्षों में प्राप्त हुए पोर्टिंग अनुरोधों की संख्या		1102.08
ग	तीन वर्षों में असामान्यकृत पोर्टिंग (टीएसपी के बंद/एक होने से)	लाख में	120.60
घ	तीन वर्षों में सामान्यकृत पोर्टिंग की मात्रा (ख—ग)		981.48
च	प्रति पोर्ट ट्रांजेक्शन लागत (क/घ)	रुपए में	6.125
छ	7वें संशोधन में निर्धारित कार्यक्षमताओं के लागू करने पर प्रति वर्ष अतिरिक्त लागत	लाख रुपए में	87.00
ज	7वें संशोधन में निर्धारित कार्यक्षमताओं के लागू करने पर प्रति पोर्ट अतिरिक्त लागत ((छx3)/घ)	रुपए में	0.27
झ	कुल प्रति पोर्ट ट्रांजेक्शन लागत (च + ज)		6.395
ट	1 प्रतिशत की दर से लाइसेंस शुल्क		0.064
ठ	प्रति पोर्ट ट्रांजेक्शन प्रभार (झ + ट)	रुपए में	6.46

नए पीपीटीसी हेतु प्रभावी तिथि

48. परामर्श प्रक्रिया के दौरान, एक हितधारक ने यह कहा है कि नए टैरिफ को भूतलक्षी प्रभाव यानि कि दिनांक 31 जनवरी, 2018 से लागू किया जाय। इस संबंध में, दोनों एमएनपीएसपी ने यह कहा है कि नए टैरिफ को भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं किया जाय तथा पीपीटीसी में 7वें संशोधन के बाद हुए परिवर्तनों को उसी तिथी से लागू किया जाना चाहिए जिस तिथी से एमएनपीएसपी के वायित्व 7वें संशोधन के अनुसार लागू किये जायेंगे। अतः प्राधिकरण ने यह निर्णय लिया है कि पीपीटीसी में वर्तमान संशोधन दिनांक 11 नवंबर, 2019 से लागू होंगे।

TELECOM REGULATORY AUTHORITY OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th September, 2019

TELECOMMUNICATION MOBILE NUMBER PORTABILITY PER PORT TRANSACTION CHARGE AND DIPPING CHARGE (SECOND AMENDMENT) REGULATIONS, 2019

(04 OF 2019)

F. No. 15-01/2019-F&EA.—In exercise of the powers conferred upon it under section 36, read with sub-clauses (ii), (iii), (iv) and (v) of clause (b) of sub-section (1) of section 11, of the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 (24 of 1997), the Telecom Regulatory Authority of India hereby makes the following regulations further to amend the Telecommunication Mobile Number Portability Per Port Transaction Charge and Dipping Charge Regulations, 2009 (9 of 2009), namely:—

1. (1) These regulations may be called the Telecommunication Mobile Number Portability Per Port Transaction Charge and Dipping Charge (Second Amendment) Regulations, 2019 (04 of 2019).
 (2) They shall come into force from the 11th November, 2019.
2. For regulation 3 of the Telecommunication Mobile Number Portability Per Port Transaction Charge and Dipping

Charge Regulations, 2009, the following regulation shall be substituted, namely: -

“3. Per Port Transaction charge: - The Per Port Transaction charge for each porting request shall be rupees six and paisa forty-six only”

S. K. GUPTA, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./240/19]

Note 1. The principal regulations were published *vide* No. 116-5/2009-MN dated 20th November 2009 (9 of 2009).

Note 2. The principal regulations were amended by Telecommunication Mobile Number Portability Per Port Transaction Charge and Dipping Charge (Amendment) Regulations, 2018 (03 of 2018) published vide File No. 15-01/2016-F&EA in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, dated 31st January, 2018

Note 3. The Explanatory Memorandum explains the objects and reasons of The Telecommunication Mobile Number Portability Per Port Transaction Charge and Dipping Charge (Second Amendment) Regulations, 2019 (04 of 2019).

EXPLANATORY MEMORANDUM

1. A subscriber can retain his existing mobile telephone number when he wishes to switch from one service provider to another or from one technology to another of the same service provider using Mobile Number Portability service within the same Licensed Service Area (LSA) as well as Pan India in any LSA. The Mobile Number Portability is operational in India since 2009, when MNP service licences were issued to two Mobile Number Portability Service Providers (MNPSPs) by DoT. DoT mandated MNP service licensees to follow the regulations/orders made or directions issued by Telecom Regulatory Authority of India (TRAI/Authority) under TRAI Act, 1997 or any instructions issued by the DoT (licensor) from time to time through amendments in licenses.
2. For the purpose of laying down the basic business process framework for implementation of MNP services in India, the Authority issued *Telecommunication Mobile Number Portability Regulations, 2009* (8 of 2009) dated 23rd September, 2009 (MNP Regulations). These regulations have been amended from time to time, latest being in 2018.
3. By notifying *The Telecommunication Mobile Number Portability Per Port Transaction Charge and Dipping Charge Regulations, 2009* dated 20th November, 2009 (MNP Charges Regulations), the Authority determined the *Per Port Transaction Charge* (PPTC) as Rs. 19/- to be paid by the Recipient Operator (RO) to the concerned MNPSP. In absence of actual historical data, this exercise was done based on estimated financial data and other information submitted by the two MNPSPs. The per port transaction charge was computed by taking the estimated total cost to the MNPSP and the estimated number of porting subscribers, over a period of 5 years. The Authority also considered the lower of the cost of the two MNPSPs for computing PPTC.
4. Further, through notification of the Telecommunication Tariff (Forty-Ninth Amendment) Order, 2009, the Authority prescribed the Per Port Transaction charge of Rs. 19/- as ceiling for the tariff that could be charged from subscriber by the recipient operator. The ‘Dipping charge’ was kept under forbearance.
5. Regulation 6(2) of the MNP Charges Regulations provides that “the Authority may review and modify the Per Port Transaction Charge and Dipping Charge at the end of one year from the date of these regulations coming into force”.
6. In 2018, ‘Per Port Transaction Charge’ was reviewed based on the actual financial and non-financial data of both the MNPSPs as available for the financial year 2016-17. Accordingly, the Authority issued the *Telecommunications Mobile Number Portability Per Port Transaction Charge and Dipping Charge (Amendment) Regulations, 2018* on 31st January, 2018 whereby per port transaction charge was reduced from Rs. 19/- to Rs. 4/- for each successful porting. However, this amendment regulation was quashed by Hon’ble High Court of Delhi *vide* its Judgement dated 8th March, 2019.
7. Subsequently, the Authority had undertaken a detailed public consultation to review the MNP process itself. The Authority issued Telecommunication Mobile Number Portability (Seventh Amendment) Regulations, 2018 on 13th December, 2018 (7th Amendment) introducing certain changes in the MNP process to ensure better services to subscribers. These primarily involve shifting responsibility of generation of Unique Porting Code (UPC) from Donor Operator (DO) to MNPSP after making real time query with database of DO and sending of SMSs to the subscriber by the MNPSP for letting the subscriber know of her/his status in the various stages of the process.

The regulation also delineated the various ancillary services² that are already being provided by the MNPSP, namely, Number return charge, Database download charge, Port cancellation charge, Subscriber reconnection charge and Non-payment disconnect charge.

8. In view of the above, the Authority initiated a public consultation process for review of the existing MNP Charges Regulations by issuing a consultation paper on 22nd February, 2019 (subsequently updated on 1st April, 2019 in view of the judgement of the Hon'ble High Court of Delhi, as mentioned above). The last date for receiving comments and counter comments from stakeholders originally was 15th March, 2019 and 22nd March, 2019, respectively. However, considering the requests of stakeholders, the last date for receiving comments and counter comments was extended up to 12th April, 2019 and 19th April, 2019 respectively. An Open House Discussion in this regard was also held on 27th May, 2019. MNPSPs and TSPs have also submitted additional comments after the open house discussion.
9. *Vide* letter dated 7th May, 2019 and subsequent reminders, the two MNPSPs were asked to provide details of capital expenditure (CAPEX) and operating expenditure (OPEX) along with copies of audited annual accounts for the financial year 2018-19. The audited financial results for the FY 2018-19 were submitted by M/s Syniverse on 22nd July, 2019. M/s MNP Interconnection Telecom Solutions India Pvt. Ltd. (MITS) submitted the audited financial results for the FY 2018-19 for MNP business on 28th June, 2019.
10. The major telecom service providers (TSPs) were also called upon to provide cost inputs for hardware and software requirement for the additional work involved due to changes introduced by 7th Amendment and probable expenditure *vide* letter dated 25th June, 2019, the responses to which were also considered by the Authority.
11. The two MNPSPs also submitted their “estimates” for the additional work required due to the 7th Amendment. The two MNPSPs were called upon to make a presentation on the architectural framework and additional hardware/software required to implement the changes in the MNP process along with the justification for the additional expenditure, which was made by both the MNPSPs on 24th July, 2019. During the presentation, it was highlighted by both the MNPSPs that the additional cost estimates given for implementation of 7th Amendment includes costs to be incurred for supporting ongoing/existing operations as well as changes envisaged under 7th Amendment. Accordingly, both were asked to segregate the two cost components. One of the MNPSPs submitted revised cost estimates after splitting cost between current operations and 7th Amendment requirements on 28th July, 2019. The other MNPSP *vide* letter dated 2nd August, 2019 informed that such segregation is not possible.
12. Based on the comments and counter comments received during the consultation process, the deliberations of open house discussion and comments received afterwards from MNPSPs and other stakeholders, the Authority issued draft “Telecommunication Mobile Number Portability Per Port Transaction Charge and Dipping Charge (Amendment) Regulations, 2019” on 16th August, 2019 (Draft Regulations). The stakeholders were requested to submit their comments on the Draft Regulations by 23rd August, 2019. However, considering the requests of stakeholders (MNPSPs), the last date for receiving comments was extended up to 28th August, 2019.
13. In paras 14 to 46, basic rationale for arriving at the Draft Regulations and the questions raised in the consultation paper have been discussed. Thereafter, in para 47, inputs received pursuant to issue of Draft Regulations (*i.e.* after 16th August, 2019) have been discussed.

Issues raised in the consultation paper and the analysis of the inputs for the consideration of decision by Authority

14. In view of the foregoing, following questions were raised in order to obtain the views of the stakeholders on review of Mobile Number Portability Per Port Transaction Charge and other charges. Written comments and counter comments of stakeholders are available at www.trai.gov.in along with the consultation paper. The subsequent paras illustrate the issues raised in the consultation paper along with the rationale for conclusion and decision of the Authority.

Whether the ‘Per Port Transaction Charges’ should continue to be calculated based on the methodology adopted by TRAI during the review done in the past? If not, please suggest methodology and supplement it with the detailed calculations indicating costs of hardware, software and other resources etc.

15. Few stakeholders have submitted that existing methodology should be continued whereas few others have suggested certain modifications. One MNPSP has *inter alia* suggested that tariff review should happen on a 5-year basis instead of an annual basis whereas the other MNPSP has suggested to review the same every three years. It has been argued by them that volume of the Mobile Number Portability used for tariff calculation

² Details of these ancillary charges are available in subsequent paras of the Explanatory Memorandum, where the issue of ancillary charges has been dealt with.

should be based on sufficiently longer period after adjusting non-recurring porting volume changes, working capital requirement to be changed to 3 months from 1 month to factor in late payments by TSPs, return on capital employed should be higher than 15%, etc. It has also been submitted by MNPSPs that all costs incurred by them should be considered and genuine business cost for which evidence is on record should not be disallowed. Further, for calculating PPTC, one of the MNPSPs mentioned that the average of both MNPSPs' (operations & business) costs should be considered instead of lower of two because both the MNPSPs operate under different environment and average of two would be best and appropriate method to adopt. They have suggested that PPTC should be stable over a period of time and review should be done after 3 years with a 6-month price implementation period. One MNPSP has submitted that "Cherry Picking" of lower costs between the two MNPSPs should not be done and costs of one MNPSP should be taken as a whole.

16. In this regard, another stakeholder has submitted that TRAI should base the PPTC on '*lower of the two*' MNPSPs' costs, as averaging the costs of two MNPSPs would not reflect the cost of an efficient MNPSP thereby penalizing the Mobile Network Operators (MNOs) by supporting inefficient MNPSP. Further, provision of bad debts in the cost calculations would result in imposition of penalty on the MNOs who make timely payments to MNPSPs. Such issues of non-payment/late payment by MNOs should be resolved between MNPSPs and MNOs under the legal framework. It has also been submitted by few stakeholders that cost of royalty/ consultancy/ licensing cannot be recovered from the MNOs for perpetuity.
17. Another stakeholder has commented that both MNPSPs are rendering their services in a monopolistic market, as there is no other supplier of MNP services in their respective zones. In such a scenario, it is essential that the charges are fixed on cost plus basis so that no undue advantage is bestowed to the MNPSPs.
18. Few stakeholders have submitted that due to substantial increase in the port volume in recent years without any significant increase in costs, the MNPSPs have already earned an excess amount after covering all the costs. They have suggested that excess recovery by MNPSPs should be adjusted in future calculations of PPTC.
19. One stakeholder has commented that cost incurred by MNPSPs for implementation of the 7th Amendment will not materially change as MNPSPs will largely be utilizing the existing network of the MNOs to cater to changed processes with marginal hardware, software and operational costs at their end. It has been submitted that additional cost would be around 1-3% of the MNPSP's present cost. In this regard, one MNPSP has commented that the assumption of 1-3% is premature and beyond the scope of the TSPs to accurately estimate these costs.
20. Another stakeholder has commented that the review should be carried out based on actual audited data of the MNPSPs and estimates on the cost to be borne under revised process. However, the Authority should keep a provision for further review after one year when the actual audited financial and non-financial data would be available. It has also been submitted that separate exercise should be done for both the MNPSPs to arrive at per port transaction considering all porting requests processed. This number should be marked up on the basis of the percentage of cancelled or rejected requests. Thereafter, a charge for ancillary services may be added to derive a per port transaction charge for both MNPSPs. It has also been suggested that the lower of these numbers should be fixed as the per port transaction charge, as Indian consumers should not suffer for inefficiencies of one MNPSP. With regard to this point, one MNPSP has commented that this approach of marking up for unsuccessful ports would reward operators which submit frivolous ports that lead to large number of errors. The cost of these failed ports will then be paid by other operators with better processes and control. Further, this approach is stated to assume that ratio of failed to successful ports is constant which is not true.
21. One stakeholder has submitted that the Authority should share the financial and non-financial data of the MNPSPs including for the years 2017-18 and 2018-19 and their projected costs for detailed consultation with other stakeholders. Both the incumbent MNPSPs contested this assertion in OHD and said that it should not be done.
22. One stakeholder has stated that there should be separate charges for UPC Request Generation in addition to the Per Port Transaction Charge as there are significant and incremental costs to comply with the 7th Amendment by the MNPSPs to receive a UPC request, query the donor operator, generate the UPC or rejection reason, send that UPC or rejection reason. In this regard, another stakeholder has commented that all costs should be subsumed under the PPTC as a separate charge for UPC Request Generation would imply that the Donor Operators will need to charge the subscribers for UPC generation activity in order to make payments to the MNPSPs, which will be detrimental to the interests of subscribers.
23. Many stakeholders have also recommended the exclusion of royalty and consultancy charges from the cost calculations by TRAI. Another stakeholder submitted that cost related to licensing and royalty should be discounted, as the same should not be applicable on a simple regulatory process for such a long duration. Stakeholders also commented on such costs being incurred in perpetuity despite the MNPSPs having gained enough expertise.

Analysis

24. The Authority analysed the submissions made and the issues involved. It decided to consider the following while arriving at the mobile number per port portability charges:
- 24.1 Unlike the year 2009 when the PPTC were initially computed in the absence of historical cost data, presently sufficient information on previous years' audited historical cost data is available with the Authority. Accordingly, the Authority decided to use audited historical cost data as the base for computing PPTC for the existing MNP process. Further, the 7th Amendment introduced certain changes in the MNP process for which the MNPs may have to make some modifications in the existing setup. Accordingly, the Authority sought the cost estimate from the stakeholders in relation to additional work involved for implementation of 7th Amendment so that the same can be appropriately considered while calculating PPTC. The responses received from all the stakeholders have been considered for computing incremental cost component of PPTC on account of additional work involved for implementation of 7th Amendment by MNPs.
- 24.2 In relation to the cost and port volume data to be considered for computing PPTC, one of the MNPs suggested to use three-year cost and port volume data to determine PPTC. The other MNP has suggested to consider port volume of last five financial years. In this regard, the Authority observed that the port volume has seen some volatility in the past few years. The porting volumes have varied from 636 lakhs in 2016-17 to 981 lakhs in 2017-18 to 576 lakhs in 2018-19. As such, the Authority decided that to get a reasonable estimate of the porting volumes and costs, it may be necessary to have an average of sufficient number of years, so that the highs and lows of particular years may not distort the results. Besides, full mobile number portability was introduced in India in July, 2015. Therefore, it would be logical to compare the porting volumes thereafter, as they would give a more reasonable and accurate estimate than comparing with the volumes earlier, when only intra-circle MNP was in place. This has also been suggested by one of the MNPs. As such, the Authority decided to take the average of the costs and porting volumes of a three-year period, from 2016-17 to 2018-19, into account for arriving at the Per Port Transaction Charge (PPTC).
- 24.3 The MNPs have also submitted that total and actual costs of each of the MNP should be considered as a whole for determining PPTC. In view of this submission and in line with TRAI's standard practise of determining tariff on the basis of costs of the economically most efficient operator, the Authority decided to take the 'lower' of the two MNPs' *total* costs (including royalty/license fee and depreciation, as indicated in the audited annual financial statements) and the associated port volume of the same MNP, for determining the PPTC. In this regard, the MNPs have contended that average of both MNPs' costs should be considered instead of lower of two as they operate in different environment. However, the Authority is of the view that an inefficient operator (with a relatively higher cost structure for same services as those provided by an efficient player with lower cost structure) should not be rewarded for its inefficiency by a higher tariff determination based on its higher cost structure. A reasonable tariff determination based on the cost structure of the efficient player would compel the inefficient player to achieve efficiency in its operations by reducing its cost. Moreover, deciding a higher tariff would be detrimental to the interest of the recipient operator/subscriber and the telecom sector as a whole.
- 24.4 One of the MNPs has also submitted that bad debts incurred by MNPs as a result of non-payment or delayed payment by the operators should also be considered as a cost component while computing PPTC. The Authority has carefully considered the issue and determines that non-payment or delayed payment between the MNPs and the operators is a commercial dispute between the two and same should not be a cost component for computing PPTC. Absorption of bad debts in computation of PPTC would disincentivise the MNPs to take good faith efforts to recover outstanding debt. Moreover, as commented by other stakeholders, provisioning of bad debts in the cost would inflate PPTC which would be akin to imposition of penalty on the MNOs who make timely payments to MNPs in the form of inflated PPTC. As such, the Authority decided to exclude Bad Debts as a cost component for the purpose of calculating PPTC.
- 24.5 The Authority also decided to take the audited financial statements of the two MNPs into account for determining the costs involved. This ensures that the costs are not based on estimation but are actual costs incurred by the MNPs in providing their services.
- 24.6 From the analysis of the inputs provided by the MNPs in the last three years, it is observed that the costs on account of consultancy and related charges for one MNP is almost 80%, which is substantial.
- 24.7 The two MNPs have suggested to increase return on capital employed (ROCE) (35% suggested by one MNP) as against present 15%. The MNPs have primarily cited tax rates, inflation, legal costs and currency fluctuation as reasons for increasing ROCE. These are discussed below:

- (a) ***Tax Rates:*** Historically, the ROCE @ 15% includes tax element at the applicable rates. Therefore, unless and until there is significant changes in the applicable tax rates, the Authority does not find any reason to adjust the ROCE rate.
- (b) ***Inflation:*** The inflation is reflected in the historical cost structure of the company which would change every year with prevailing rate of inflation in the economy. In the present case, the Authority has already considered the historical costs of the MNPSPs to determine tariff and therefore, there is no further need to adjust ROCE for inflation again. Further, the inflation is already represented in the existing ROCE.
- (c) ***Legal costs:*** These have already been considered as part of the historical cost of the MNPSPs and making another provision for the same in ROCE would result in double accounting of legal costs.
- (d) ***Currency fluctuation:*** The quantum of currency fluctuation loss, as reflected in the audited financial statement of the MNPSPs, is insignificant and therefore, it would not impact the overall ROCE determination. Further, currency fluctuations may result in loss as well as profit depending upon on the exchange rate movement and therefore, there is no merit in considering currency fluctuation in such exercises.
- 24.8 As such, the Authority determines that ROCE @ 35% is exorbitant and 15% is a reasonable return on the capital employed. Therefore, in line with the existing practice, the Authority has considered return on capital employed @ 15% for determining the total cost.

While calculating ‘Per Port Transaction Charge’, whether the total number of MNP requests received by MNPSP or successfully ported numbers be considered? Please justify your response.

25. In this regard, most of the stakeholders have commented that while calculating PPTC, total number of MNP requests received by MNPSP should be considered. Few other have commented that only successful porting requests should be considered for calculating PPTC. In this regard, one stakeholder has commented that with the implementation of the 7th Amendment, gap between porting requests and successful port would reduce and therefore the same will not have any substantial financial impact on the MNPSPs. Another stakeholder has commented that MNPSPs have to incur cost even in case of an unsuccessful porting which are generally more expensive than successful ones. It was also submitted that PPTC based on successful ports will be higher as compared to PPTC based on total port requests. Therefore, the customers who successfully port will end up subsidising and paying for the free porting attempts made by non-serious subscribers or subscribers who submit incorrect documents.

Analysis

26. In this relation, the Authority observed that the gap between total porting requests and successful porting has been reducing over the years and is likely to reduce further after the 7th Amendment comes into force. Besides, the MNPSP has to incur costs even on unsuccessful porting requests. Further, in many cases, the failure of a porting request could be due to reasons beyond the control of the MNPSP. As such, the Authority decided to take each porting request into consideration for determining the PPTC. As already mentioned, most of the stakeholders have also suggested to consider total number of port requests.

Determination of PPTC

27. Based on the above considerations, the Authority arrived at the following PPTC for the existing services provided by MNPSPs:

Particulars	Unit	Amount
Employee Cost [#]	Rs in Lacs	1318.37
Administration and other costs [#]		2452.93
Consultancy/ royalty charges [#]		1049.27
Depreciation & Amortisation [#]		94.09
RoCE @ 15% [#]		1096.53
Total Cost* for 3 years	Rs in Lacs	6011.19
Actual porting for 3 years	in Lacs	1102.08
Porting charges per port	in Rs	5.45

** Based on the total cost of the concerned MNPSP excluding bad debts/provision for bad debts and foreign exchange losses (Even if foreign exchange losses are considered, it would not impact the PPTC computation significantly). This also includes Return on Capital Employed (RoCE) @ 15%. Capital employed has been calculated as the sum of net book value of fixed assets, total capital work in progress and net working capital (current assets – current liabilities) as at the end of the financial year.*

Aggregate value for three financial years (i.e. 2016-17, 2017-18 and 2018-19)

Incremental Component of PPTC

28. The 7th Amendment, as discussed earlier, provides for some changes in the flow of the MNP process like UPC generation by MNPSP instead of DO after real-time query from the DO database and the MNPSP sending status notifications to the subscriber. The MNPSPs may incur some CAPEX and OPEX to implement changes envisaged under 7th Amendment. Accordingly, for computation of incremental component of PPTC on account of additional work involved for implementation of 7th Amendment, the Authority sought cost estimates from MNPSPs as well as TSPs in relation to additional work involved for implementation of 7th Amendment. However, the cost estimate given by the MNPSP, whose total costs are lower, includes cost to be incurred for supporting ongoing/existing operations as well as additional work envisaged under 7th Amendment. Despite repeated requests, the segregation of the two cost components have not been provided to the Authority by the said MNPSP. Accordingly, the Authority has used the data provided by the stakeholders, including MNPSPs and TSPs (who are presently engaged in UPC generation and associated processes), for determining incremental component of PPTC on account of additional work involved for implementation of 7th Amendment.
29. The MNPSPs have submitted that they need to add personnel to address incremental responsibilities. However, the Authority determines that the additional work involved on account of 7th Amendment would largely be automated with no or minimal human intervention and the existing personnel deployed by MNPSPs in the current operations would be sufficient to undertake the additional work envisaged under 7th Amendment.
30. The MNPSPs may have to do some minor software and hardware modifications in their existing system. During the presentation mentioned above, one of the MNPSPs has even submitted that in the short-term, changes required for 7th Amendment will be made in the current system itself. This implies that software and hardware changes required to implement the changes should be minimal. Another MNPSP has submitted that for implementation of 7th Amendment, it would require total 4 units of hardware components (i.e. one storage unit, one tool for ITSM/network and system monitoring and 2 units of SMPP servers). Accordingly, the Authority finds that the additional work involved for implementation of 7th Amendment is not likely to result in substantial additional CAPEX and OPEX to be incurred by MNPSPs.
31. The cost should be minimal if the marginal capacity in the present hardware is utilised using open source software or existing licensed software to implement the changes required as per the 7th Amendment. Even if it is allowed that new additional hardware and separate licensed software is used to implement the changes, the total cost on account of additional work involved for implementation of 7th Amendment would be approximately Rs. 87 lakhs per annum. In calculating this, the Authority has considered depreciation of the capital expenditure on hardware and software development/licensing as per the provisions of the Companies Act, 2013, along with related operating expenditure. Considering an average porting request volume of 367 lakhs per annum (i.e. average of last three financial years), the Authority determines that an additional cost of 23 paisa per port request is sufficient to cover the additional requirements of hardware and software, if required by the MNPSPs. This would also adequately cover the cost of handling UPC requests by the MNPSPs under the 7th Amendment. Thus, the PPTC to cover the entire MNP process, as per the 7th Amendment to MNP regulations worked out to:

Particulars	Unit	Amount
Total Cost for 3 years	Rs. in Lakh	6011.19
No. of porting requests received	in Lakh	1102.08
Per Port Transaction Cost	in Rs.	5.45
Incremental component of PPTC	in Rs.	0.23
Total Per Port Transaction Cost	In Rs.	5.68
Licence Fee @1%	in Rs.	0.06
Per Port Transaction Charge	in Rs.	5.74

32. The MNSPSS have also submitted that the Authority should review the tariff on a 3-year basis instead of an annual basis as it would provide stability and continuity to the business. The Authority has considered this and notes that for determining incremental component of PPTC, actual cost data related to software and hardware

requirements is not available and the same would be available only after these changes are implemented and the Bills of Material generated/expenses incurred. One of the MNPSPs has also submitted that all the costs of complying with 7th Amendment as well as UPC volume are not known at the time of launch. The other MNPSP has also submitted that tariff can be reviewed in the intervening period in case of any exigency. As such, the Authority has decided to consider reviewing the PPTC after one year, if required.

Review of Ancillary Charges

33. During the consultation process preceding the 7th Amendment to MNP Regulations, issue of ancillary service charges was raised for the comments of the stakeholders. After examination of the comments of the stakeholders, the Authority noted that the provision for ancillary service charges shall remain in the regulations subject to consultation at the time of defining the actual amount of charges or otherwise will be subsumed in per port transaction charges.

34. Accordingly, following question was raised for comments of the stakeholders:

Should the charges for ‘Per Port Transaction’ and ‘ancillary services’ be determined separately or consolidated charges. Please justify your response along with detailed calculations indicating cost of hardware, software, other resources and overhead etc. in addition to the rationale for adoption of the method suggested by you.

35. The stakeholders were required to provide comments on the two options as described below for determining ‘Per Port Transaction Charge’ and other charges termed as ancillary charges:-

- (i) Based on the cost incurred, separate charges for ‘Per Port Transaction Charge’, ‘Number Return Charge’, ‘Database download charge’, ‘Port cancellation charge’, ‘Subscriber Reconnection Charge’ and ‘Non-payment disconnect charge’ may be determined; or alternatively,
- (ii) Only one charge i.e. ‘Per Port Transaction Charge’ may be made applicable and cost of all other charges termed as ‘ancillary charges’ may be subsumed in the ‘Per Port Transaction Charge’.

36. In this regard, most of the stakeholders have submitted that there should be a consolidated per port transaction charge subsuming the charges for ancillary services also. One stakeholder has commented that Number Return, Subscriber Reconnection and Non-payment disconnection should be charged separately, whereas Port cancellation charge should be included in PPTC. Further, Database Download to be provided free of charge. One of the MNSPS also proposed to set a quota per operator for database download to avoid egregious abuse by frequent downloads.

Analysis

37. In the Telecommunication Mobile Number Portability (Seventh Amendment) Regulations, 2018, the provision of ancillary service charges payable to MNPSP have been made in the regulation for the activities to be performed as mentioned below:

- (a) **Number Return Charge** for facilitation of returning the mobile number to Number Range Holder after disconnection due to any reason including non-payment.
- (b) **Database download charge** for downloading the Number Portability Database by the Access Provider.
- (c) **Port cancellation charge** for execution of ‘Port withdrawal’ request of the subscriber of Donor operator.
- (d) **Subscriber Reconnection Charge** for facilitation of reconnecting the ported subscriber of Recipient Operator in its network.
- (e) **Non-payment disconnect charge** for facilitation of disconnection of the mobile number of the postpaid subscriber who has not cleared the dues of the Donor Operator after porting his number.

38. In relation to separate charges for ancillary services, it is noted that PPTC has been determined on the ‘cost-plus’ basis. This implies that all the costs of the MNPSP in providing ‘all’ its services are taken into account while arriving at the PPTC. It may be noted that the ancillary services, as listed out in the 7th Amendment to the MNP Regulations, are already being provided by the MNPSPs as brought out in the following table:

Table: Information of ancillary activities for the period Jan-Dec 2018

MNPSP Zone	No. of Number Return requests received	Total instances of Database download	No. of Port cancellation requests received	No. of Subscriber Reconnection requests received	No. of NPD requests received
Zone I	9351497	954	107517	787266	1620505

Zone II	7691841	1499	14972	NIL ³	480104
Total	17043338	2453	122489	787266	2100609
Avg. per month	1420278	204	10207	65606	175051

39. The Authority has used a ‘Cost Plus’ approach in determining the PPTC. As such, while factoring in the total costs in providing services for previous three financial years, the costs of providing the ancillary services are also included. In considering the costs of previous three financial years, the costs of any software and hardware changes made by the MNPSPs has also been considered. The Authority, therefore, determines that separate charges for providing ‘ancillary’ services are not necessary as the costs for providing all the services have been considered in arriving at the PPTC. Further, considering the present volume of database download, the Authority decided that setting any quota for database download by the TSPs is not required.

Review of Dipping Charges

40. The following question was raised for the comments of the stakeholders:

Whether the Dipping charge, which is presently under forbearance, needs to be reviewed? If yes, suggest the methodology to determine the rate of dipping charge. Support your response with justification.

41. Most of the stakeholders have commented that Dipping charges should continue to be under forbearance and any service provider that requires the dipping services from the MNPSPs can avail the same on mutually agreed terms with the MNPSPs. One of the stakeholders has commented that till date, no operator has used this service and therefore, the MNPSPs should be allowed to remove the related infrastructure that adds to additional cost.
42. After analysing the comments and counter comments received from various stakeholders, the Authority decided that the Dipping charge will continue to be under forbearance. Dipping charges may be mutually decided by the MNPSP and the access provider or the ILDO who desires to utilise the query response system of the MNPSP.

Review of Porting charge payable by subscribers

43. The Telecommunication Tariff (Forty-Ninth Amendment) Order, 2009 prescribed the Per Port Transaction Charge, as provided under the MNP Charges Regulations, as ceiling for the tariff that could be charged from subscriber by the recipient operator. Accordingly, following question was raised for the comments of the stakeholders:

Whether the porting charge payable by the subscriber to the recipient operator should continue to be prescribed as a ceiling charge as per the current practice. If no, please suggest methodology and various consideration for calculating porting charge payable by subscribers.

44. Almost all the stakeholders have suggested to continue the existing practice. In this regard, one of the stakeholders has commented that due to fierce competition in the telecom market, porting charges, which is payable by customer generating porting request, are being absorbed by the recipient operators.
45. Another stakeholder has commented that recently due to closure of few TSPs and ongoing consolidation in the sector, the subscribers had to resort to forced porting and therefore, in the interest of the subscribers, no charges should be payable for forced porting.
46. After analysing the issues at hand, the Authority determined that the existing practice of Per Port Transaction Charges shall continue to be the ceiling for the porting charges payable by the subscriber to the recipient operator.

Issues raised by stakeholders' post issue of Draft Regulations

47. The stakeholders have largely reiterated their previous submissions on various issues and a few new comments have also been submitted. Various issues raised and the deliberations on the same is as follows:

- 47.1 One of the MNPSPs has contended that whilst deciding on the total ongoing costs for existing operations as well as the changes envisaged under the 7th Amendment, the only appropriate stakeholders are the MNPSP's and not the Telecom Service Providers, who technically would lack the technical know-how to assess and/ or comment on the intricate and complex process involved in services being rendered by MNPSP's, let alone the costs. The Authority disagrees with the view taken by the said MNPSP as TSPs are also an equally important stakeholder of this entire consultation process. Besides, the primary additional work being assigned to the MNPSPs, that of UPC generation, is currently being handled by the

³ Zone II has not provided any data related to subscriber reconnection requests received

- TSPs. In any case, it would be fair to ask the TSPs to offer their comments on the price they are supposed to pay. The very basis of the consultation process is to seek comments from stakeholders at different ends of the issue.
- 47.2 The TSPs have reiterated that cost of royalty/consultancy/licensing cannot be recovered for perpetuity as the MNPSPs have gained substantial expertise in last 8-9 years. Accordingly, the TSPs have requested the Authority to exclude these costs from the calculation of PPTC and only cost of production/rendering services should be included such as hardware, software, operation and maintenance. However, the Authority decided to consider the historical audited cost data available from the annual accounts of the MNPSPs.
- 47.3 The MNPSPs have also reiterated that costs of carrying bad debt are real costs and they should be included in the overall costs. The MNPSPs are of the view that non-payment of dues by various TSPs is affecting their overall financial health. In this regard, the Authority notes that as per Regulation 15 of the MNP Regulations, the Recipient Operator (RO) is required to pay the billed PPTC amount to the MNPSPs within fifteen days of receipt of the bill or within such other time limit as may be mutually agreed upon. If the RO do not adhere to these regulations, it becomes a dispute between the two service providers and either of the party is free to approach the Hon'ble Telecom Dispute Settlement and Appellate Tribunal (TDSAT) seeking appropriate redressal. The Authority is therefore of the view that bad debts cannot be considered as a cost component while calculating PPTC.
- 47.4 One of the MNPSP has also suggested that there should be severe penalty on late payments by TSPs to MNPSPs so that the impact of bad debt is minimized. The Authority has carefully considered the suggestion of the said MNPSP and is of the view that the same cannot be accepted primarily for two reasons *i.e.* *Firstly*, the imposition of penalty for non-payment or delayed payment is beyond the scope of present consultation process as the same cannot be covered under the MNP Charges Regulations, *Secondly*, as already stated in the previous paragraph, the MNPSPs while approaching the Hon'ble TDSAT may always seek appropriate remedy for non-payment or delayed payment by the TSPs. Another MNPSP has suggested to allow the MNPSPs to cease providing MNP services to the defaulting TSPs. The Authority has considered this suggestion and again cannot accept the same primarily for two reasons *i.e.* *Firstly*, allowing MNPSPs to cease providing MNP services to the defaulting TSPs is beyond the scope of present consultation process, *Secondly* and more importantly, it would harm the interest of the willing subscriber who wants to port his number to the said TSP.
- 47.5 The MNPSPs further submitted that the detailed breakup of total cost of Rs. 6011.19 Lacs was not provided in the Draft Regulations, however, the same is essential to know what all genuine costs have been omitted in computing PPTC. One MNPSP has stated that in the spirit of transparency, cost breakups considered by the Authority should be shared with the MNPSPs so that they are aware of the costs allowed and /or disallowed. It is however, noted that the said MNPSP during the open house consultation claimed that there are some costs which can be shared and some costs which cannot be shared publicly because of the fact that those are costs which are "commercially competitive" for them and it would hampers their principals to bid in other countries.
- 47.6 The said MNPSP has also submitted that despite several representations, the Authority has disallowed genuine costs negatively and unjustifiably. It has also recommended that the Authority should appoint a third-party international consultant who has domain expertise to review and ascertain costs, porting volume and the resultant tariff. It is reiterated that the Authority has considered total costs as available from the audited financial statements of the MNPSPs with few exclusions like bad debts/provision for bad debts and currency fluctuations loss (the reason for the same has been detailed sufficiently). Further, the Authority has considered total cost (including royalty/license fee and depreciation, as indicated in the audited financial statements) of the more economical of the two MNPSPs, for determining the PPTC. In other words, total cost and port volume data of the MNPSP with lower per port transaction cost has been considered for determining the PPTC.
- 47.7 A revised table showing detailed breakup of the costs (Rs. 6011.19 lacs) has also been added in the Explanatory Memorandum. It would be more appropriate if the MNPSPs were to review its cost structure and identify the areas of improvement to achieve cost efficiency.
- 47.8 The MNPSPs have again contended that return on capital employed @ 15% is not sufficient and the same must be measured after taxes to grant a sufficient return on capital employed. One of the MNPSP has suggested to use mark up on costs @ 25%. This issue was already adequately addressed in the Draft Regulations and has been elaborated in the Explanatory Memorandum. The Authority reiterates that the MNPSPs have not furnished any compelling reason for reconsideration of the ROCE rate. Therefore, in line with the existing practice, return on capital employed @ 15% has been considered for determining the total cost. Another MNPSP has suggested to provide the basis of computation of capital employed.

Accordingly, it is clarified that capital employed has been calculated as the sum of net book value of fixed assets, total capital work in progress and net working capital as at the end of the financial year.

- 47.9 The MNPSPs have further submitted that reduction in PPTC would render providing ancillary services free of cost. Further, database download rate should be fixed at Rs. 15000/- for each download after 2 free downloads every month. In this regard, the Authority determines that the concerned MNPSP has made contradictory submissions. On the one hand the said MNPSP admitted that costs of these services were already included in the historical costs whereas on the other, it claimed that reduction in PPTC would effectively render such services free of cost. This is not true as the Authority has considered all the relevant costs incurred by the MNPSPs (except few heads as already explained earlier) to determine PPTC which include costs for providing 'ancillary' services. Therefore, the Authority does not find any reason to change the Draft Regulations in this respect.
- 47.10 It has also been contended by the MNPSPs that the Authority has arbitrarily taken a figure of Rs. 87 lacs as cost of 7th Amendment completely ignoring actuals being incurred towards capital costs for Hardware and Software development. The MNPSPs have further contended that the Authority has not given a rationale for its assumption that substantial addition of CAPEX and OPEX is not required by MNPSPs. On the other hand, few TSPs are of the view that additional cost/investment would not be more than 1-3% of the MNPSPs present costs. One of the TSP has suggested that with open source software this cost of Rs. 87 lakhs will be reduced to 25%. The rationale and basis of computation of incremental component of PPTC on account of implementation of 7th Amendment was elaborated in detail in the Draft Regulations. In this regard, it is reiterated that the additional work involved on account of 7th Amendment would largely be automated with no or minimal human intervention and the existing personnel deployed by MNPSPs in the current operations would be sufficient to undertake the additional work envisaged under 7th Amendment. As elaborated above, the data provided by the stakeholders, including MNPSPs and TSPs (who are presently engaged in UPC generation and associated processes), for determining incremental component of PPTC on account of additional work involved for implementation of 7th Amendment has been used. Further, in relation to the contention of the concerned MNPSP that actual data has not been considered, it is stated that none of the MNPSP has provided data related to actual expenditure (software and hardware requirements) incurred on account of additional work envisaged under 7th Amendment. Therefore, the Authority has decided to review the PPTC and other charges after one year when audited historical data would be available.
- 47.11 One of the MNPSP has submitted that the Authority has not considered the need of separate charges for UPC generation from the PPTC. It has also been submitted that apart from UPC generation and SMS processing, there are certain other changes to the porting process to be catered to under the 7th Amendment, which will also drive up costs and the same have not been considered (*e.g.* non-payment suspension and reconnection). In this relation, it is noted that the computation of incremental component of PPTC as proposed in the Draft Regulations covered the estimated cost towards all the additional work associated with the implementation of 7th Amendment including handling UPC requests and therefore, the amended tariff of PPTC under these regulations adequately covers these costs to be incurred by the MNPSPs under the 7th Amendment. In any case, the Authority has decided to review the PPTC after one year when audited historical cost data would be available for the additional work performed by the MNPSPs.
- 47.12 One of the MNPSP has submitted that considering the significant reduction in the porting revenue, the Authority should enable the MNPSPs to obtain data from both MNP zones and provide dipping services to 3rd parties under commercial terms mutually agreeable between the MNPSP and 3rd parties. The said MNPSP has submitted that this may allow the MNPSPs to share certain assets and resources across multiple services. While the cost of the MNPSP will not change, the allocation of some of those costs can be reduced by allocating a portion of them to dipping. In this regard, the Authority determines that the tariff related to Dipping charges is under forbearance and the present issue raised by the MNPSP is beyond the scope of this consultation process.
- 47.13 One of the MNPSP has requested to delay the implementation of the new PPTC tariff till 1st January, 2020. It has been further submitted that the new tariff should be implemented on the 1st of the month following implementation of the 7th Amendment by all stakeholders. The Authority has considered the difficulty expressed by the MNPSPs in the billing system due to changes in tariff during the month. However, the Authority determines that the amended tariff specifically covers the incremental component for implementation of 7th Amendment and therefore, the 7th Amendment and the amended tariff should come into force simultaneously. The difficulty expressed by MNPSPs can be addressed easily in their billing systems.
- 47.14 A TSP has sought clarification from the Authority in relation to the applicable PPTC rate during the period from 31st January, 2018 (*i.e.* when the previous amendment to MNP Charges Regulations were notified) to

the date when the present amendment would come into force due to subsequent quashing of the said amendment by the Hon'ble High Court of Delhi. In this regard, the Authority is of the view that the claims and liabilities of the parties depend upon the findings/ observations given by the Hon'ble High Court of Delhi *vide* its judgement dated 8th March 2019. In case of any dispute between the parties, arising due to difference of opinion on the issue, the aggrieved party may approach the appropriate forum for redressal of its grievances.

- 47.15 The TSPs have also requested the Authority to address the issue of competition in the MNP services by ending lack of choice to TSPs as well as subscribers in choosing its MNPSP by opening entire 22 service areas to both the MNPSPs. Another stakeholder has advocated the adoption of Blockchain to create more efficient processes and lower the cost of operation. The Authority has considered these submissions and agrees that promoting competition in MNP services would improve efficiency and innovation in the MNP services. However, these suggestions cannot be addressed in the present consultation process. However, the Authority would continue to take measures for facilitating competition and promoting efficiency in the telecom services in general and MNP services in particular.
- 47.16 The MNPSPs have submitted that the port volume considered by the Authority for computing PPTC is not representative of current volumes or volumes estimated for the future on which PPTC would be applied. The MNPSPs have reiterated to ‘normalize’ the port volume data for one-time spikes on account of closure/merger of the operations by the TSPs, as the one-time spikes are unlikely to be repeated in the future. One of the MNPSP also suggested a tiered pricing structure to minimize risk of using a high or low number for deriving PPTC.
- 47.17 The Authority examined the suggestions about tiered pricing structure. Such approach would involve many subjective assumptions and would be difficult to implement both for MNPSPs and TSPs, hence is not a practical option. The Authority also considered the representation of the MNPSPs and decided that the one-time exceptional porting due to closure/merger of TSPs needs to be taken into consideration for the porting volumes to be a fair reflection of the normal porting that is likely to happen in the absence of such ‘forced portings’. The market has stabilized between the major players to some extent and abnormal spikes due to closures and mergers are unlikely to happen in the near future. As such, the porting volume being crucial in determining PPTC, it is essential that the porting volumes being considered are as ‘normal’ as possible. The Authority had ‘normalized’ the porting volumes to an extent in the Draft Regulations by taking an average of three years to smoothen the spikes in particular years, but present trend in porting volumes is indicated better by excluding the ‘forced portings’, especially as the relevant information/data is available with TRAI.
- 47.18 The two MNPSPs submitted their own estimates of the one-time spikes due to closure/merger of TSPs. The relevant MNPSP has projected 190.76 lakh ports as ‘extraordinary’ *i.e.* due to closure/merger of TSPs during the period, based on the criteria that the spikes were greater than the average trend. However, it would be too simplistic to assume all the spikes in porting to be due to ‘forced portings’, arising out of closure/merger of TSPs. More than 95% of the mobile connections in India are pre-paid connections with a balance in the account, which the subscriber would like to utilize before porting the number. Further, some of these port requests would be due to factors other than closure /merger of the TSPs e.g. bad quality of service, better tariff/service offered by other TSPs, *etc.* As such, the Authority decided to arrive at a relatively more objective criteria of arriving at the ‘forced porting’ volume, based on the information/data submitted by the MNPSPs and TSPs to TRAI during the relevant months. The TSPs reported to TRAI about the date of closure/merger of operations in the relevant LSAs. The MNPSPs also reported to TRAI about the porting volumes TSP-wise and LSA-wise. As such, the authority has decided that the port-out volumes of a TSP happening from the month of closure of operations (as reported to TRAI) in the relevant LSAs till the month that TRAI directed the TSPs and MNPSPs to complete the porting of subscribers, will be considered as ‘forced portings’, and the porting volumes shall be ‘normalized’ to that extent.
- 47.19 Upon considering the above-mentioned criteria, it is found that out of total port volume of 1102.08 lakhs considered by the Authority for the relevant MNPSP in the Draft Regulations, 120.60 lakh is on account of one-time spikes due to closure/merger of TSPs. Thus, the ‘normalized’ port volume for the MNPSP is 981.48 lakhs (*i.e.* 327.16 lakhs in a year). Comparing the ‘normalized’ port volume with the present volume of porting (the Authority has considered the port volume from January to July’ 2019, which is available as of now), it is observed that the annualized port volume based on the porting data since January’ 2019 for the concerned MNPSP is 313 Lakhs. As such, the ‘normalized’ port volume as arrived at by the Authority fairly represents the prevailing port volume. Therefore, the Authority decided to consider the ‘normalized’ port volume for the calculation of PPTC.

47.20 Based on the above, the revised calculation of PPTC is as follows:

S. No	Particulars	Unit	Amount
A	Total Cost for 3 years	Rs. in Lakh	6011.19
B	No. of porting requests for 3 years	in Lakh	1102.08
C	No. of exceptional porting (<i>i.e.</i> due to closure/merger of TSPs) for 3 years		120.60
D	Normalized port volume for 3 years (B-C)		981.48
E	Per Port Transaction Cost (A/D)	in Rs.	6.125
F	Additional cost per annum due to implementation of functionalities prescribed by 7 th Amendment	Rs. in Lakh	87.00
G	Additional per port cost to implement the functionalities prescribed by 7 th Amendment ((F*3)/D)	in Rs.	0.27
H	Total Per Port Transaction Cost (E+G)		6.395
I	Licence Fee @1%		0.064
J	Per Port Transaction Charge (H+I)	in Rs.	6.46

Effective date for new PPTC

48. During the consultation process, one stakeholder submitted that the new tariff should be implemented with retrospective effect i.e. 31st January, 2018. In this regard, the MNPSPs have submitted that the new tariff should not be implemented with retrospective effect and any changes in PPTC pursuant to 7th Amendment should be made effective at the same date as the obligations of the MNPSPs under the 7th Amendment becomes effective. The Authority has decided that the present amendment to the PPTC would come into effect from 11th November, 2019.